bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2081 युगाब्द 5126 कुल पृष्ठ– 42, फरवरी प्रथम अंक 2025, वर्ष–36 : अंक–13

वर्तमान

कमल ज्योति

विकसित भारत 2047

₹20

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री भूपेन्द्र सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक
नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
Vartman Kamaljyoti
@bjpkamaljyoti

सनातन गर्व, महाकुंभ पर्व

सम्पादकीय

दिल्ली विजय का संदेश

भारत की राजधानी दिल्ली प्रदेश में भाजपा की 27 वर्षों बाद जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस जीत को विकास, विजन, विश्वास की जीत बताया। आम आदमी पार्टी की हार को आडम्बर, अराजकता, अहंकार की हार कहा।

भाजपा 'सुशासन' के बल पर ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' के संकल्प को साकार रूप दे रही है। उ0प्र0 उपचुनाव परिणाम की बात करें तो जून 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद सबसे अधिक चर्चा अयोध्या संसदीय क्षेत्र में भाजपा की पराजय की हुई, जहाँ श्री रामजन्मभूमि पर दिव्य, भव्य राम मंदिर का हिन्दू समाज का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था।

अयोध्या की हार और अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहे जाने से सनातन समाज में दुःख, निराशा और क्षोभ था। मिल्कीपुर उपचुनाव को सनातनी हिन्दुओं ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था।

राजनैतिक दल के रूप में भाजपा ने मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए बेहद आक्रामक रणनीति तैयार की और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार मिल्कीपुर का दौरा किया। जब योगी जी मिल्कीपुर जाते थे तब सपा मुखिया, सांसद का बयान आता था कि योगी जी जितनी बार मिल्कीपुर आयेंगे भाजपा का वोट प्रतिशत उतना ही घटेगा।

जनता ने विपक्ष के नकारात्मक विचारों के एजेंडे को नकारते हुए विकास और सुशासन का साथ दिया। जनता को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि स्थानीय विकास के लिए सत्तारूढ़ भाजपा का विधायक ही आवश्यक है। मिल्कीपुर की जनता ने सपा के परिवारवाद और जातिवाद को नकार दिया है। परिणाम से यह भी साफ हो गया है कि योगी का **'बटेंगे तो कटेंगे'** का नारा जातिवाद के विरुद्व हिंदुत्व की राजनीति को ताकत दे रहा है। इस विजय से भाजपा के लिए हिंदुत्व की राजनीति के पथ पर आगे बढ़ना संकल्प से सिद्धि को मिलना है।

मिल्कीपुर सीट पर भाजपा को तीसरी बार जीत मिली है ।इससे पहले 1991 और 2017 में जीत मिली और अब 2025 में चंद्रभानु पासवान ने सपा के गढ़ में भगवा परचम लहराने में सफलता हासिल की है। मिल्कीपुर सीट का गठन 1967 में हुआ था और 1969 में तत्कालीन जनसंघ हरिनाथ तिवारी विधायक चुने गये थे ।इसके बाद 1974 से 1989 तक यह विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का अभेद्य किला बन गया ।1991 में राम लहर में मथुरा प्रसाद तिवारी ने भाजपा से जीत दर्ज की फिर 2012 तक यहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2017 में मोदी लहर में भाजपा के बाबा गोरखनाथ विजयी रहे। यह अलग बात है कि इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने बाबा को पराजित किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवाबर बनाया था और वह जीत गये। तभी से भाजपा पर लगातार दबाव बनता जा रहा था कि किसी न सिकी प्रकार से यह सीट हर हाल में जीतकर दिखानी है और योगी जी की टीम ने यह काम कर दिखाया है।

चुनाव से पूर्व प्रयागराज महाकुम्भ –2025 में योगी कैबिनेट ने एक साथ गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर मीडिया जगत और जनमानस में इस बात का संदेह पूरी तरह से दूर कर दिया कि योगी कैबिनेट व भाजपा में आपस में कोई मतभेद व मनभेद है। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा भदरसा दुष्कर्म कांड के बहाने सपा पर हमलावर रही। चुनावों के बीच ही वहां पर एक बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का एक मामला सामने आया उसके बाद विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरने का असफल प्रयास किया। इस घटना को लेकर सभी दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट करके राजनीतिक तापमान को गरमाने का असफल प्रयास किया था। सनातनी कुंभ पर अखिलेश जी लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। जबकी विश्व का जनमानस सुव्यवस्था से सन्तुष्ट हो त्रिवेणी में डुबकी लगा रहा है। स्नान का आकड़ा पचास करोड़ के पार पहुंच रहा है। ऐसे में तय है कि देश **''विकसित भारत''** बनाने के लिए देश की जनता संकल्पबद्ध है।

राजकुमार

भारत की विकास यात्रा का 'अमृत काल'

संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

अभी दो माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नयी ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबासाहेब आंबेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूं।

इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ, भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पुण्य स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे पर अपना दुःख व्यक्त करती हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोया है। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वो लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूं।

भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है।

मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पांच लाख छत्तीस हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है।

मेरी सरकार गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक़ देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक दो करोड़ पच्चीस लाख सम्पत्ति कार्ड जारी किए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीनों में इक्तालीस हज़ार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है।

जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए **"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष"** अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए अस्सी हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा।

छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए कर दी गई है।

मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष पांच सौ कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिये जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है।

सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने **'त्रिभुवन'** सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में पच्चीस हज़ार बस्तियों को जोड़ने के लिए सत्तर हज़ार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आज जब हमारा देश अटल

जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब इकहत्तर वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही हैं, जिनमें पिछले छह माह में ही सत्रह नई वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है।

"वन नेशन–वन इलेक्शन" और **"वक़्फ़ अधिनियम संशोधन"** जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं।

मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है।

विकसित भारत के विजन में... जनभागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है... देश की आर्थिक उन्नति का रोडमैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नॉलाजी की ताकत है, और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधार है।

मेरी सरकार के प्रयासों के बल पर भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।

विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान, इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है।

सरकार reform, perform और transform के अपने संकल्प को तेज गति से आगे बढ़ा रही है।

मेरी सरकार का मंत्र है–सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ...और इस मंत्र का एक ही लक्ष्य है – विकसित भारत का निर्माण।

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पचास प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है।

जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है तभी विकास सार्थक होता है। यही अंत्योदय की वो भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है।

गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है, वो गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों को राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसी अनेक योजनाओं ने गरीब को ये भरोसा दिया है कि वो सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने नियो मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है, जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है।

भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा देश उतनी ही ऊंची उड़ान भरेगा। मेरी सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है।

सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि हैं। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय, आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा।

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पचास प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है।

मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसा कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है।

उड़ान योजना ने लगभग डेढ़ करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया है। जन औषधि केंद्र में 80 प्रतिशत रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से, देशवासियों के 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है।

राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। अब देश में पचहत्तर वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को, जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बनी है।

यह इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस अकैडमी में भी महिला कैडेट्स की भर्ती शुरू हो गई है।

हमारी बेटियाँ आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी

गौरवान्वित कर रही हैं।

मैं भारत की संसद के माध्यम से देश की नारी–शक्ति को विशेष बधाई देती हूं।

पिछले एक दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं ने उठाया है। आज हमारा युवा स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फ़ील्ड में देश का नाम रोशन कर रहा है। MY Bharat पोर्टल के ज़रिये लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ रहे हैं।

पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोज़गार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले दो वर्षों में सरकार ने, रिकॉर्ड संख्या में दस लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। मेरी सरकार ने देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स वातावरण बनाने की दिशा में खेलो इंडिया स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानि TOPS, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जैसे कई कदम उठाए हैं। दिव्यांगों के लिए ग्वालियर में विशेष खेल केंद्र खोला गया है। भारत की टीमों ने चाहे ओलंपिक हो, या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर हम सशक्त युवाशक्ति का निर्माण कर रहे हैं।

पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोज़गार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं।

विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावरहाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पचास हज़ार करोड़ रुपए की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन स्थापित किया गया है।

मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस जैसी परिस्थितियों से उबारने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति के साथ काम किया है। कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं Resilience दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने Ease of doing business को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन नेशन वन टैक्स की भावना के तहत जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई, जिसका फायदा सभी राज्यों को मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के कारण अब बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के प्रॉडक्ट्स पर भी **'मेड इन इंडिया'** के लेबल्स दिखने लगे हैं।

भारत के छोटे व्यापारी गाँव से लेकर शहरों तक, हर जगह आर्थिक प्रगति को गति देते हैं। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर दे रही है।

मेरी सरकार ने दस वर्षों में प्रगति के जो नए अध्याय लिखे हैं, उनमें से एक स्वर्णिम सोपान भारत की डिजिटल क्रांति का भी है। आज भारत डिजिटल टेक्नॉलाजी की फ़ील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5G सर्विसेस की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत की यूपीआई टेक्नॉलाजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50 प्रतिशत से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहा है।

मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नॉलाजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहा है।

गाँव में भी बैंकिंग सेवाएँ और UPI जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नॉलाजी उपलब्ध है। भारत में पिछले 10 साल में बने पांच लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की दर्जनों सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। मेरी सरकार ने लोगों के जीवन पर सरकार का प्रभाव कम करने के लिए ई–गवर्नेंस को महत्व दिया है। डिजिलॉकर की व्यवस्था ने लोगों को कभी भी, कहीं भी अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पाने और दिखाने की सुविधा दी है।

तेज़ी से डिजिटाइज़ होते हमारे समाज में आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय साइबर सिक्योरिटी है। डिजिटल फ्रॉड, साइबर–क्राइम और डीप फेक जैसी टेक्नॉलाजी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी बनी है। इन साइबर–क्राइम को नियंत्रित करने के

लिए कई कदम उठाए गए है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोज़गार की संभावनाएं हैं।

मेरी सरकार साइबर सिक्योरिटी में दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। इसके फलस्वरूप भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टियर–1 स्टेटस प्राप्त कर लिया है।

वाढवण में भारत के पहले डीप वाटर मेगा पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। छिहत्तर हज़ार करोड़ की लागत से बनने वाला ये पोर्ट विश्व के शीर्ष दस पोर्ट्स में से एक होगा।

मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर – श्रीनगर – बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है जो विश्व का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज है। साथ ही आँजी ब्रिज, देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है।

शिंकुन ला सुरंग पर काम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में पूरी होने पर ये विश्व की सबसे ऊँची सुरंग होगी। इससे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच बारहमासी संपर्क बना रहेगा। भारत का एविएशन सेक्टर तेज़ी से विकास कर रहा है। देश की एयरलाइन कम्पनियों ने सत्रह सौ से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले विमानों के परिचालन के लिए हम एयरपोर्ट्स का विस्तार कर रहे हैं। पिछले एक दशक में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है।

मेरी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को मिल रहा है। आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है।

मेरी सरकार बहु–आयामी एवं समरस–सर्वस्पर्शी विकास की नीतियों पर काम करती आई है। इसीलिए, मेरी सरकार ने जितना बल फ़िज़िकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दिया है उतने ही सघन प्रयास सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रांति के लिए भी किए हैं।

समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। अस्पताल, इलाज और दवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है।

देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एक लाख पचहत्तर हज़ार आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं।

देश में कैंसर मरीज़ों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनेक कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है।

सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग नौ करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

मेरी सरकार के प्रयासों से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को काफी सफलता मिली है। इससे होने वाली मृत्यु दर अब घटकर छह प्रतिशत रह गयी है।

भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है।

वर्ष 2023–24 में रिकॉर्ड तीन सौ बत्तीस मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है। और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादक है।

सरकार ने खरीफ़ और रबी फ़सलों के एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की है। पिछले एक दशक में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की गई है।

पिछले 6 महीने में फसलों की जलवायु अनुकूल, बायो – फॉर्टिफाइड और अच्छी उपज देने वाली एक सौ नौ उन्नत प्रजातियाँ किसानों को सौंपी गई हैं।

देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के दायरे का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा।

देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स को स्वीकृति दी गई है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है।

इस वर्ष की शुरुआत में ही, किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज की अवधि को बढ़ाया गया है।

मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए ग्यारह एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है।

जब हम राष्ट्र के विकास और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, तो वास्तव में हम राष्ट्र के नागरिकों की क्षमता एवं उपलब्धियों का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। आज देश के विकास में सबका साथ है, इसीलिए हम देश के सही सामर्थ्य का अनुभव कर पा रहे हैं।

मेरी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को मिल रहा है।

आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है।

'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' और **'पीएम–जनमन योजना'** इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

देश भर में स्थापित चार सौ सत्तर से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से लगभग सवा लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। पिछले दस वर्षों में आदिवासी बहुल इलाकों में तीस नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।

विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग पाँच करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

जनजातीय विरासत को सहेजने के लिए भी मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की एक सौ पचासवीं जयंती का पर्व पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण कसौटी, देश का संतुलित विकास है। किसी क्षेत्र में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वो विकास में पीछे छूट रहे हैं।

मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इन्हीं भावनाओं को समझा, उनके दिल से दूरियों का भाव समाप्त किया।

दस से अधिक शांति समझौते कर सरकार ने अनेक गुटों को शांति के मार्ग से जोड़ने का काम किया है।

पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में, पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया।

पूर्वोत्तर के विकास के साथ–साथ सरकार ने देश के **"पूर्वोदय"** यानि पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य–योजना पर काम शुरू कर दिया है जिससे रोज़गार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में विकास की कई परियोजनाएं प्रारम्भ कर उन्हें राष्ट्र की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। जम्मू कश्मीर में लोक सभा चुनाव एवं विधान सभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

मेरी सरकार के प्रयासों से आज विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत ने ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई है।

सभी एशियाई बौद्ध देशों को आपस में जोड़ने के लिए, मेरी सरकार ने पहली एशियाई बुद्धिस्ट कांफ्रेंस का आयोजन किया। पिछले वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बैठक का आयोजन भी भारत में हुआ जिसमें एक सौ चालीस देशों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरा विश्व आज भारत की योग परंपरा को अंगीकार कर रहा है।

प्रगति की भव्य इमारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने Reform, Perform और Transform के ऐसे ही तीन मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये शब्द पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं।

सरकार ने संविधान के लागू होने से पहले बने कानूनों की विस्तृत समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधित किया जा रहा है ताकि पूरा तंत्र वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके।

सरकार अब तक पंद्रह सौ से अधिक पुराने अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर चुकी है। गुलामी के कानूनों को हटाकर दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता लागू की गई है। **'जन–विश्वास'** और **'जन–भागीदारी'** के साथ मेरी सरकार जनता का जीवन सुगम बनाने पर कार्य कर रही है।

विवादों को निपटाने के लिए 'विवाद से विश्वास' की पहल की गई है।

इसी भावना के साथ सरकार ने चालीस हज़ार से अधिक नियमों को कम या सरल किया है और पैंतीस सौ प्रावधानों को अपराधमुक्त किया है।

मेरी सरकार ने देश के अत्यन्त पिछड़े इलाकों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारम्भ कर सुशासन का एक अनूठा प्रयोग किया है। इस कार्यक्रम से इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विभिन्न मापदंडों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट में इस पहल की बहुत सराहना की गई है। इस सफलता से प्रेरित होकर अब देश के पांच सौ आकांक्षी ब्लॉक में भी समग्र विकास हेतु अभियान प्रारम्भ किया गया है।

वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तम्भ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाहे जी–7 समिट हो, क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ हो या जी20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नीयत पर पूरे विश्व ने भरोसा जताया है।

आज बड़े से बड़े वैश्विक मंच पर भी भारत अपने हितों को मजबूती के साथ आगे रखता है। जी–20 का सफल आयोजन और दिल्ली डिक्लेरेशन इसका उदाहरण है। तीसरी ग्लोबल साउथ समिट, भारत आसियान समिट और भारत कैरीकॉम समिट में हमने ग्लोबल साउथ से जुड़े विषयों को अभिव्यक्ति दी है। हमने समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत का **"विजन फॉर फ्यूचर"** रखा है।

इसी माह मेरी सरकार द्वारा भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया।

प्रवासी भाई–बहनों की सुविधा–सहूलियत हमारी प्राथमिकता है, इसलिए छह नए दूतावास और चार नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है।

विश्व बंधु की छवि मजबूत करते हुए विश्व में कई आपदाग्रस्त इलाकों में भारत ने तुरंत सहायता भरा हाथ बढ़ाया है।

भारत ने कई देशों के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर साझा किया है और जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं।

मेरी सरकार वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय ले रही है। हम देश को ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स की तरफ ले जा रहे हैं।

2030 तक पांच सौ गीगावॉट नॉन फॉसिल फ़्यूल एनर्जी क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बीते छह महीनों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पचहत्तर हज़ार करोड़ रुपये की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक साढ़े सात लाख घरों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

"राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन" के तहत आठ लाख करोड़ रुपए का निवेश और छह लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा।

हम परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। मेरी सरकार, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लायी है, ताकि पुराने वाहनों का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा हो और इससे भी रोजगार के नए अवसर सृजित हों।

इसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर **"एक पेड़ मां के नाम"** अभियान प्रारम्भ किया गया। इस पहल में करोड़ों देशवासियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान की पूरे विश्व ने सराहना की है। हमारा भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहां भिन्न–भिन्न राज्य, भिन्न–भिन्न क्षेत्र, भिन्न–भिन्न भाषाएँ हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है – भारत।

और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है – विकसित भारत! आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं, और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुये एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए, हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं, और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों! जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियाँ 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगी।

विकसित भारत का अर्थ संकल्प 2025-26

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2025–26 पेश किया। तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन 'कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है' कथन को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2025–26 में प्रस्तुत किया। इसमें 'सबका विकास' लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया हैं।

इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जो इस तरह से हैं–

क) गरीबी से मुक्ति

ख) शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा

ग) बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य तक पहुंच

घ) शत–प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार

ङ) आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं

च) देश को **'फूड बास्केट ऑफद वर्ल्ड'** बनाने वाले किसान

केन्द्रीय बजट 2025–26 में विकास को बढ़ावा के लिए सरकारी प्रयासों को जारी रखने, समग्र विकास को सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, परिवारिक भावनाओं को बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा किया गया। इस बजट में प्रस्तावित विकास, उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया है।

बजट में भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामिण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, एसएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा के ईंजन हैं। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथप्रदर्शक के रूप में रखा गया है।

पहला ईंजनः कृषि

बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ 'प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना'की गई है। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है जहां उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने, दीर्घ–अवधि और लघु–अवधि, ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया।

१ लाख रूपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी

राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु–क्षेत्रीय 'ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण' कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक अवसरों का सृजन करते हुए जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान देना है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। केन्द्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन तीन दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे।

बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु उपायों की भी अवधारणा तैयार की गई है। कृषि और इससे सम्बद्ध गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए इसमें अन्य उपायों के साथ कपास उत्पादकता के लिए एक पांच वर्षीय अभियान और उच्च पैदावार करने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिटों के माध्यम से मिलने वाले ऋण की

सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।

दूसरा इंजन: एमएसएमई

वित्त मंत्री ने विकास के लिए एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया, क्योंकि यह क्षेत्र हमारे निर्यात का 45 फीसदी है। एमएसएमई को व्यापक स्तर पर उच्चतर कुशलता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है। इसके अलावा गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी उपायों की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार की उद्यमी पांच लाख महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया। यह अगले 5 वर्षों के दौरान करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करेगी।

तीसरा इंजन: निवेश

निवेश को वृद्धि का तीसरा इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने लोगों, अर्थव्यवस्था और अभिनव में निवेश को प्राथमिकता दी।

लोगों में निवेश के अंतर्गत, उन्होंने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ

भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ब्रॉडबेंड कनेक्टविटी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना को विद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के डिजिटल स्वरूप को प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 'मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर दी वर्ड' विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से हमारे युवाओं को युक्त करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना की जाएंगी।

500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस में एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

बजट में घोषणा की गई कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल, गिग श्रमिकों के पहचान पत्र बनाने के साथ–साथ ई–श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी।

अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत बुनियादी ढांचा–संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड में परियोजनाएं के तीन वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेंगे।

राज्यों के लिए पूंजीव्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है।

नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी का लाभ लेने के लिए दूसरी परिसम्पत्ती मौद्रिकरण योजना 2025–30 की भी घोषणा की।

'जनभागीदारी' के माध्यम से ग्रामीण पाइप के माध्यम से जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, संचालन और मरम्मत पर ध्यान देने के साथ वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन का विस्तार किया गया है।

सरकार 'विकास केन्द्रों के तौर पर शहरों, के रचनात्मक पुर्नविकास और जल एवं स्वच्छता' के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष का गठन करेंगी।

अभिनव में निवेश के अंतर्गत निजी क्षेत्र परख अनुसंधान, विकास और अभिनव पहल को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने शहरी योजना को लाभ देने हेतु बुनियादी भू–स्थैतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय भू–स्थैतिक अभियान का प्रस्ताव दिया।

बजट में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम् अभियान का प्रस्ताव दिया गया। ज्ञान साझेदारी के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था के एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष का भी प्रस्ताव दिया गया।

चौथा इंजन: निर्यात

श्रीमती सीतारमण ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, 'भारत ट्रेडनेट (बीटीएन)' का व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया गया है।

वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़े रखने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार उद्योग 4.0

से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए दूसरी श्रेणी के शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रारूप का भी प्रस्ताव दिया गया है।

सरकार जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद सहित एयरकार्गों के लिए बुनियादी ढांचे और वेयरहाउसिंग के उन्नयन हेतु सुविधा प्रदान करेगी।

ईंधन के रूप में सुधार

इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए पिछले दस वर्षों से ज्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलैस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, लगभग 99 फीसदी रिटर्न स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए उन्होंने कर विभाग की 'विश्वास प्रथम जांच बाद में' वचनबद्धता को दोहराया।

वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास

'कारोबार में आसानी' की दिशा में सरकार की त्वरित वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अनुपालन में आसानी, सेवाओं के विस्तार, मजबूत नियामक परिवेश को बनाने, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहन देने और पुराने कानूनी प्रावधानों के गैर–अपराधीकरण को आगे बढ़ाते हुए भारत में सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र की व्यापकता में संरचनात्मक बदलाव का प्रस्ताव दिया।

केन्द्रीय बजट में विकास के चार ईंजनों की पहचान की गई है- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात

समूचे भारत में प्रीमियम निवेश करने वाली कम्पनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 फीसदी से 100 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

श्रीमती सीतारमण ने सिद्धांतों पर आधारित सरल नियामक प्रारूप और उत्पादकता एवं रोजगार को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव दिया, उन्होंने 21वीं सदी के लिए आधुनिक, लचीले, लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित नियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित चार विशेष उपायों का प्रस्ताव दियाः–

I- विनियामक सुधार हेतु उच्चकस्तनरीय समिति

- सभी गैर–वित्तीतय क्षेत्र संबंधी विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंसऔर अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्चतस्तसरीय समिति
- खासतौर पर निरीक्षणों और अनुपालनों के मामलों में कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए विश्वास आधारित आर्थिक शासन को मजबूत बनाना और परिवर्तनकारी उपायों को अपनाना
- एक वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुमत करना
- राज्यों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना

II- राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक

- प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद की भावना की बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए एक निवेश अनुकूल सूचकांक का शुभारंभ 2025 में किया जाएगा

III- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के अंतर्गत व्यवस्था

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत, वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूलेंकन करने के लिए एक तंत्र स्थोपित किया जाएगा।
- यह तंत्र जबावदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा।

IV- जन विश्वा्स बिल 2.0

- विभिन्नल कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर–आपराधिक बनाना।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को प्रत्येाक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास किया जाएगा कि केन्द्री य सरकार का ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। इसके साथ ही अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृघत ब्यौरा एफआरबीएम विवरण में दिया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2024–25 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8 प्रतिशत है जबकि बजट अनुमान 2025–26 में राजकोषीय

घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

संशोधित अनुमान 2024-25

वित्त मंत्री ने बताया कि उधारियों के अलावा कुल प्राप्ति यों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये है। उन्हों ने ज्याोदा जानकारी देते हुए बताया कि कुल व्यंय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से पूंजीगत व्याय लगभग 10.18 लाख करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान 2025-26

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025–26 में, उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्युउय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

भाग ख

राष्ट्र निर्माण में मध्यमवर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताते हुए केन्द्रीय बजट 2025–26 में नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आय कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण प्रतिवर्ष 12.75 लाख रुपये होगी। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप नए कर संरचना के तहत सरकार को प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्वण का परित्याग होगा।

संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और एक लाख आवासीय ईकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ स्वामिह निधि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रर मोदी के नेतृत्वर में सरकार ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए कई महत्वीपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रत्यीक्ष कर प्रस्तीवों में मध्य म वर्ग पर ध्यांन केन्द्रित करते हुए व्यतक्तिगत आयकर में सुधार, टीडीएस/टीसीएस को तर्कसंगत बनाना, अनुपालनों के बोझ को कम करते हुए स्वैच्छिक अनुपालनों को प्रोत्सा्हित करना, व्यसवसाय करने की सुगमता और निवेश और रोज़गार बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्सातहन शामिल हैं।

नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है:

कुल वार्षिक आय	कर की दरें
0–4 लाख रुपए	शून्य
4–8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8–12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12–16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16–20 लाख रुपए	20 प्रतिशत
20–24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

टीडीएस/टीसीएस की दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्या ज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रस्तावित है। अन्यच कदमों में अब धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है और उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर–पैन मामलों पर ही लागू होंगे। विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब को गैर–आपराधिक कर दिया गया था अब टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्वैच्छिक अनुपालन को अद्यतन करने की सुविधा को लेकर लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधी ब्यौरों को अद्यतन किया। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए, अब किसी भी कर–निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरण दाखिल करने की समय–सीमा को मौजूदा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। छोटे धर्मार्थ न्याय/संस्थाओं की पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्ताव है। करदाताओं को स्वामित्व वाली

सम्पत्तियों के लिए बिना किसी शर्त के ऐसी दो सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्य के लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्तोव किया गया है। पिछले बजट में प्रस्तुत की गई विवाद से विश्वास योजना को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और इसके द्वारा लगभग 33,000 करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने विवादों का निपटारा किया है। वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देते हुए 29 अगस्त , 2024 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से किए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्युवस्था का प्रस्ताव है।

व्यवसाय करने की सुगमता के तहत, अंतरण मूल्य की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन–देन के मामलों में आर्म्स लेन्थ मूल्यो निर्धारण करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। यह योजना सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप होगी। अंतरराष्ट्रीय विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने की दृष्टि से सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया जा रहा है।

रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने हेतु उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, जो ऐसी निवासी कम्पनी को सेवाएं प्रदान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है। देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय स्टार्ट–अप इको–सिस्टम में 5 वर्षो तक निगमन की अवधि का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख को 5 वर्ष बढ़ाकर 31, मार्च, 2030 तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा–शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए बजट में : (i) सात टैरिफ दरों को हटाने, (ii) प्रभावी शुल्क दायित्वं बनाए रखने के लिए कुछ मदों प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों को छोड़कर और (iii) एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव है।

आयातित दवाईयों पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारी बीमारियों और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टूम ड्यूटी (बीसीडी) से पूरी तरह छूट दे दी गई है। पेटेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 13 नई दवाओं सहित 37 दवाईयों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है, अगर ये दवाएं मरीज को मुफ्त दी जाती है।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य, संवर्धन, 25 विशेष खनिजों जिनकी घरेलू उपलब्धता नहीं है उन्हें भी सहायता देने के लिए जुलाई, 2025 से बीसीडी से मुक्त कर दिया गया है। 2025–26 के बजट में कोबाल्ट पाउडर और उसके कबाड़, लीथियम आयरन बैट्री के कबाड़, लैट, जिंक और 12 अन्यक मुख्यल खनिजों को भी छूट दी गई है। घरेलू कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मशीनरी में दो अन्य शटल लैस लूम्सय को भी छूट दी गई है। बजट में आगे कहा गया है कि बुने हुए कपड़े जो 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, जिन्हें 20 प्रतिशत कर दिया गया है या 115 किलोग्राम से जो ज्याददा है, जो 09 टैरिफ लाइन्स को कवर करती है, उनके बीसीडी में भी संशोधन किया गया है।

प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इंटरेक्टिव फ्लेट पैनल डिस्पले (आईएफपीडी) को 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है और ओपन सैल्स को 5 प्रतिशत कम किया गया है। ओपन सैल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओपन स्टेंडस को बीसीडी के हिस्से के रूप में छूट दी गई है।

देश में लीथियम आयन बैट्री के निर्माण को बढावा देने के लिए, ईवी बैट्री निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन की बैट्री के निर्माण के लिए 28 अतिरिक्ति पूंजीगत वस्तुओं को भी पूंजीगत वस्तुओं को दी जाने वाली छूट की सूची में जोड़ा गया है।

केन्द्री य बजट 2025–26 में कच्चे माल, कलपुर्जो, जहाज के निर्माण में आने वाले सामान और दोबारा उपयोग में आने वाले सामान पर अगले 10 वर्षों के लिए बीसीडी की छूट भी जारी रहेगी।

वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12-75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा

देश सर्वांगीण विकास की दिशा में : मोदी

आम बजट सत्र के प्रारंभ मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है–

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि।
मंत्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोस्तुते।।

मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं, समृद्धि और कल्याण भी देती हैं। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है, और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनता है।

ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है, और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है, और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा, कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरी टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न–भिन्न स्तर के संदर्भ में हो। हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोडमैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक दिन, कल सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में ये सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है, तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है, राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं।

हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20–25 साल की आयु के नौजवान हैं, जब वे 45–50 साल के होंगे, तब वो विकसित भारत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्था में उस जगह पर बैठे होंगे, कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारी, हमारे टीनएजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 1942 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी, आजादी के जंग में, और उसके फल, 25 साल के बाद जब पीढ़ी आई, उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे, उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल, आजादी का जश्न बनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा, और इसलिए इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे, विशेषकर के जो युवा सांसद हैं, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरुकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है, वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है।

मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा–आकांक्षाओं पर इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों को तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक, शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है, कि जिसके एक–दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकड़ी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। 10 साल से, 2014 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां इसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से, कोई चिंगारी नहीं हुई।

दिल्ली को विकसित भारत की 'विकसित राजधानी' बनायेंगे : मोदी

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिल्ली विधान सभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह को संबोधित किया और दिल्ली के विकास के लिए भाजपा सरकार के विजन को जनता से साझा करते हुए दिल्ली के विकास को अवरुद्ध करने वाली विपक्षी पार्टियों पर जम कर प्रहार किया। कार्यक्रम में भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित कई पार्टी पदाधिकारी, दिल्ली के भाजपा सांसद, कई नवनिर्वाचित विधायक एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत **"यमुना मैया की जय"** के नारे के साथ की।

श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को **आप–दा** से मुक्त कराने का है। दिल्ली के विकास की बड़ी बाधा दूर हो गई। चुनाव से पूर्व मैंने हर दिल्लीवासी के नाम पत्र भेज कर प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को अवसर दीजिए और दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर प्यार दिया। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए सिर झुकाकर नमन करता हूं। आपके इस प्यार को विकास के लॉन्ग रूट पर हम लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों का ये प्यार और विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके ये कर्ज चुकाएगी।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की आज की विजय ऐतिहासिक है। ये सामान्य विजय नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता ने आप–दा को बाहर कर दिया है। करीब एक दशक की आप–दा से दिल्ली मुक्त हुई है। दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है तथा आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आप–दा की हार हुई है। उन्होंने कहा कि जिन्हें दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका आज सच से सामना हो भी गया है। दिल्ली के जनादेश से स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्ट कट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्ट कट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में ये टीस थी दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की। आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली की युवा पीढ़ी और 21वीं सदी में पैदा हुए युवा पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुसाशन देखेंगे। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया। अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है।

> **आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई 'आप'दा की हार हुई है। दिल्ली की जनता ने आप-दा को बाहर कर दिया है।**

यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज के नतीजों का एक दूसरा पक्ष भी है। दिल्ली कोई एक शहर नहीं बल्कि ये मिनी हिंदुस्तान है। विविधताओं से भरे भारत का ये लघु रूप है। दिल्ली 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के विचार को जीती है। यहां दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत के

लोग है। आज इसी विविधता वाली दिल्ली ने भाजपा को प्रचंड जनादेश का आशीर्वाद दिया है। आज दिल्ली का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कमल न खिला हो। हर भाषा और हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। चुनाव में मैं जहां गया, गर्व से कहता था कि मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं।ये पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा और ताकत दे दी। मैं पूर्वांचल के लोगों का पूर्वांचल के सांसद के नाते विशेष आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली वालों को मेरी गारंटी है, सबका साथ–सबका विकास– पूरी दिल्ली का विकास। दिल्ली के विजय उत्सव के साथ–साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। सभी ने भाजपा के लिए भारी संख्या में मतदान किया है।

पार्टी	भाजपा+		AAP		कांग्रेस	
	सीट	वोट%	सीट	वोट%	सीट	वोट%
2025	48	47.15%	22	43.57%	0	6.34%
2020	8	38.51%	62	53.57%	0	4.26%
2015	3	32.19%	67	54.34%	0	9.65%
2013	31	33.07%	28	29.49%	8	24.55%

Source- Election Commission of India

श्री मोदी ने कहा कि आज देश तुष्टिकरण नहीं, बल्कि भाजपा के संतुष्टिकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। टकराव तथा प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया है। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक रुकावट आप सब दिल्लीवासियों ने दूर कर दी है। दिल्ली में आप–दा वालों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका, झुग्गी वालों को घर लेने से रोका, आयुष्मान भारत का लाभ भी नहीं मिलने दिया। अब दिल्ली की जनता ने गवर्नेंस का साफ संदेश दिया है। दिल्ली ने पहले का जमाना देखा है। गवर्नेंस नौटंकी, प्रचार और प्रपंच का मंच नहीं है। जनता ने फिर और डबल इंजन की सरकार को चुनाव है। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे।

आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है। पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है, वहां सुशासन है, विकास है और विश्वास है।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है, वहां सुशासन है, विकास है और विश्वास है। एनडीए का हर उम्मीदवार, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल, मणिपुर, बिहार हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है। एक जमाने में यूपी की कानून–व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती थी। कितना बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। हमने संकल्पबद्ध होकर काम किया। महाराष्ट्र में हर साल सूखे के कारण हमारे अन्नदाता पर कितना बड़ा संकट आता था। हमने जल मित्र जैसे अभियान चलाकर हर किसान तक पानी पहुंचाया। हरियाणा में बिना खर्ची–बिना पर्ची सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। भाजपा सुशासन का नया मॉडल तैयार कर रही है। पूर्वोत्तर में हमने विकास की नई धारा से लोगों को जोड़ा है। गुजरात में खेती–किसानी कभी मुश्किल थी। वहीं गुजरात आज एग्रीकल्चर पावरहाउस बन गया है। बिहार का हाल आपको पता था, नीतीश जी बदलाव लाए। बदलाव तभी लाए जब एनडीए की सरकार बनी।

NDA की गारंटी मतलब सुशासन की गारंटी। इसका फायदा गरीब को भी होता है और मिडिल क्लास को भी। दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले भाई–बहन और मिडिल क्लास ने भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है। हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा है। दिल्ली में हमने सबसे पहले मेट्रो का काम शुरू किया। अन्य शहरों में एयरपोर्ट मेट्रो और अर्बन डेवलपमेंट पर काम किया। स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से छोटे शहरों के लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आयुष्मान के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मैंने ओडिशा, महाराष्ट्र या हरियाणा हर राज्य में नारी शक्ति से किए हर वादे को पूरा किया है। आज इन राज्यों में करोड़ों माताओं–बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

मैं दिल्ली की मातृ शक्ति से कहता हूं कि मैं उनसे किया हर वादा पूरा करूंगा। ये मोदी की गारंटी है, यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी है।

श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोग टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा से त्रस्त रहे हैं। अब यहां भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। पहली बार दिल्ली–एनसीआर के हर प्रदेश में भाजपा का शासन आया है। आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। ये सुखद संयोग है। इन सभी क्षेत्रों में आजादी के बाद पहली बार एकसाथ भाजपा की सरकारें हैं। हमारी कोशिश होगी कि आनेवाले समय में मोबिलिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। इस क्षेत्र के नौजवानों को तरक्की के नए–नए रास्ते मिलेंगे। दिल्ली भारत का गेटवे है। इसलिए इसे देश का सर्वश्रेष्ठ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए।

दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना की गोद में पनपा है लेकिन, दिल्ली की 'आप-दा' ने इस आस्था का अपमान किया। मैंने संकल्प लिया है कि यमुनाजी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे।

माँ यमुना की दुर्दशा पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माँ यमुना हमारी आस्था का केंद्र हैं। तभी तो कहते हैं कि नमो नमस्ते यमुना सदा त्वम। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना को नमस्कार करते हैं। उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी है। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुनाजी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना की इस पीड़ा को देखकर आहत हो रहे हैं लेकिन दिल्ली की आप–दा ने इस आस्था का अपमान किया, लोगों की भावनाओं–आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने संकल्प लिया है कि यमुनाजी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं कि काम कठिन है, लंबे समय का है, गंगा जी को देखिए राजीव गांधी के जमाने से चल रहा है। समय कितना ही क्यों न लगे, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, उनका आशीर्वाद हमारे संकल्प को लगेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि आप–दा वाले यह कहकर राजनीति में आए थे कि राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे का बयान सुन रहा था। वे काफी समय से इन आप–दा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। इस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। यह देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। ये खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट और दूसरों को भ्रष्टाचार का मेडल देते थे, वे खुद बेईमान निकले। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी, तब ये आप–दा वाले शीशमहल बना रहे थे। आप–दा वालों ने अपने घोटाले छिपाने के लिए साजिशें रचीं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि पहले विधानसभा सत्र में ही ब|ळ की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है।

कांग्रेस पर कड़ा हमला करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। ये लोग खुद गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। कांग्रेस एक के बाद एक सहयोगियों को खत्म कर रही है। आज की कांग्रेस

सहयोगियों की भाषा और एजेंडा को चुराने में लगी हुई है। उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है, जिस पर सपा और बसपा अपना मानती है। मुलायम सिंह जी समझ गए थे। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी की जमीन को खाने में जुट गई है। कांग्रेस ने ऐसा ही हाल जम्मू–कश्मीर, बंगाल में भी अपने सहयोगियों का भी किया। दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है, उसका बंटाढार होना तय हो जाता है। राजनीति का अध्ययन करने वालों पर एक काम छोड़ता हूं। आपने देखा कि 2014 के बाद कांग्रेस के नेताओं ने 5–7 साल तक हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, माला पहनना, उन्हें लगा ऐसे भाजपा के वोट बैंक में सेंध मारेंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों ने उन्होंने यह रास्ता बंद कर दिया। अब राज्यों की अलग–अलग पार्टियों करती है। ये सोच दुनिया में अपनी ही सोच का आर्थिक–सामाजिक और राजनीतिक निजाम लाना चाहती है। यही वजह है कि मैंने एक लाख नौजवानों को राजनीति में आने को कहा है। देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। राजनीति को नए आइडिया, राजनीति और चिंतन की जरूरत है। अच्छे नौजवान बेटे–बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। सफलता–असफलता अपनी जगह पर है लेकिन देश को धूर्तता तथा मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। देश का तेजस्वी युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता–मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। हमें राजनीति में नयापन लाना है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की ये ऐतिहासिक जीत हमारे लिए नई जिम्मेदारी लेकर आई है।

पर उनकी नजरें हैं। पार्टियां समझ गई होंगी कि ये उनको ही खा रहे हैं। प्छक् गठबंधन के दल अब कांग्रेस का कैरेक्टर समझने लगे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने छीना, कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। दिल्ली में प्छक् गठबंधन के दलों ने मिलकर कांग्रेस के वोट बैंक को रोकने की कोशिश की है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ पूरा प्छक् गठबंधन था। वे कांग्रेस को रोकने में सफल रहे, लेकिन आप–दा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये अर्बन नक्सलियों की भाषा है। ये देश में, समाज में अराजकता लाने की भाषा है। आप–दा भी उसी सोच को आगे बढ़ा रही थी। ये सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक भाजपा रिफॉर्म–परफॉर्म की गारंटी देती है। इसमें दिल्लीवासी जुड़ जायेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन और तेजी से आएगा। हम मिलकर दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे। मैंने हमेशा जिस मंत्र को जिया है, जिसे मैं स्मरण करता हूं, वो है – हमें हमेशा, जब–जब विजय मिले अपनी नम्रता को कभी छोड़ना नहीं है। विवेक, समाजसेवा के भाव को नहीं छोड़ना है। हम सत्ता सुख के लिए नहीं सेवा भाव के लिए आए हैं। हम शक्ति और समय सेवा के लिए खपा देंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। दिल्ली और एनसीआर के विकास के सपने सोचे हैं, उसे पूरा करके रहें। सभी देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आभार, दिल्ली वासियों का फिर से आभार। सभी को बधाई। उन्होंने "यमुना मैया की जय" और "भारत माता की जय" के साथ ही अपने उद्‌बोधन को पूरा किया।

दिल्ली साधुवाद आभार!

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केंद्रीय कार्यालय में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित समारोह को संबोधित किया। श्री नड्डा ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली की जनता के प्रति आभार और दिल्ली प्रदेश के जुझारू कार्यकर्ताओं के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक लगातार विजय हासिल की है और जनता ने 'मोदी की गारंटी' पर लगातार बारंबार मुहर लगाई है। विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में दिल्ली की जनता स्पष्ट संदेश दिया। लोकसभा में दिल्ली की जनता ने सभी सातों सीटों पर भाजपा को विजयी बनाने के बाद अब विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर कमल खिलाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि दिल्ली की दिल में मोदी बसता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। देश को भ्रष्टाचार और जातिवाद से निकालकर विकास और प्रगति की ओर अग्रसर किया है। गरीब, पीड़ित और शोषित वर्ग के जीवन में सुधार लाने के लिए आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उन पर इस चुनाव में जनता ने अपनी मुहर लगाई है। भारतीय राजनीति में पहले लोभ–लुभावने वादों का बोलबाला था। जनता को लुभाने के लिए बड़े–बड़े वादे किए जाते थे, जो बाद में भुला दिए जाते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस परंपरा को बदलते हुए राजनीति में रिपोर्ट कार्ड की परंपरा शुरू की। उन्होंने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया, और जो नहीं कहा था, वह भी पूरा किया। यही कारण है कि आज जन–जन की जुबान पर एक ही नारा है 'मोदी की गारंटी, यानि गारंटी पूरी होने की गारंटी।'

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का यह चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान नेताओं और उनकी पार्टी को करारा जवाब है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल दिया है। जो लोग चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर उसे खत्म करने के वादे करते थे, वही लोग आज दिल्ली के हर घर के सामने कूड़े का ढेर लगाने के जिम्मेदार हैं। जिन्होंने शुद्ध पानी देने का वादा किया था, उन्होंने ही दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने पर मजबूर कर दिया। जो लोग वर्ल्ड क्लास शिक्षा के नाम पर जनता को छलते थे, उन्हीं लोगों ने स्कूलों में दो–तिहाई बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई से वंचित किया। जिन लोगों ने बेहतर सड़कों का वादा किया था, उन्होंने दिल्ली की जनता को गड्ढों से भरी सड़कों पर चलने को मजबूर किया। यही कारण है कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्हें

दिल्ली में लोकसभा में सभी 7 सीटों पर कमल खिलाने के बाद विधानसभा में 48 सीटों पर जीत दिलाकर जनता ने यह दिखा दिया कि दिल्ली के दिल में मोदी बसते हैं।

केवल वादे करने वाली पार्टी की जरूरत नहीं है। जनता ने आम आदमी पार्टी को करारी हार देकर घर बैठाया है। श्री नड्डा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री, झूठ बोलने की एनसाइक्लोपीडिया और झूठ की संपदा वाली आपदा भी है। यह पार्टी भ्रष्टाचार की नई–नई तकनीकें निकालने वाली पार्टी है और वास्तव में आप–दा ही है। दिल्ली की जनता ने चुनाव में 'आप'दा को करारी हार दिखाकर यह साफ कर दिया है कि इस ऐतिहासिक जीत के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली फिर से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी। जो खुद को "कट्टर ईमानदार" कहते थे, वे ही कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सभी जेल की हवा खा चुके हैं। आम आदमी पार्टी की हार यह स्पष्ट करती है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें जेल भेजने पर अपनी मुहर लगा दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में जिस तरह से महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और व्यवसायियों ने साथ दिया है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत–बहुत बधाई देता हूं। आप–दा के अलावा एक ऐसी पार्टी है जो अपने स्कोर में लगातार शून्य पर बनी हुई है, चाहे वह 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी का स्कोर हमेशा शून्य ही रहा है।

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की नई-नई तकनीकें निकालने वाली पार्टी हैं। 'आप-दा' वाली यह पार्टी झूठ की फैक्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया है।

आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था, "आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।" दिल्ली की जनता ने भी आप–दा को सहने से इनकार कर दिया और दिल्ली को बदलकर रख दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को जो विश्वास मिला है और जो वादे हमने जनता से किए थे, उन्हें भाजपा ने अपने शासित राज्यों में पूरा किया है और अब दिल्ली में भी इन्हें पूरा किया जाएगा। अब भाजपा की सरकार दिल्ली में भी विकास करके दिखाएगी। श्री नड्डा ने अंत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया और दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए आशीर्वाद के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया।

'आ-पदा' मुक्त दिल्ली- मोदीमय भारत!

डॉ. सौरभ मालवीय

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अटूट विश्वास रखती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विजय इस बात का भी प्रमाण है कि जनता को गुजरात मॉडल पसंद आ रहा है। इसलिए मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा का विजय रथ निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। विशेष बात यह है कि दिल्ली की जनता से निःशुल्क विद्युत, जल एवं बस सेवा आदि सुविधाओं को नकारते हुए भाजपा को बहुमत दिलाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में दो सौ यूनिट विद्युत और महिलाओं के लिए बस सेवा निःशुल्क की हुई थी। किन्तु जनता ने इन निःशुल्क सेवाओं के स्थान पर भाजपा की नीतियों का चयन किया। अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कार्य करेगी।

दिल्ली में लगभग सत्ताईस वर्ष पश्चात भाजपा सत्ता में लौटी है। देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा और इसके सहयोगी दल ही सत्ता में हैं, जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा एवं पुडुचेरी सम्मिलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की विजय का संपूर्ण श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने न केवल तीसरी बार निरंतर केंद्र की सत्ता में भाजपा को बनाए रखा है, अपितु राज्यों में भी पार्टी को विजय दिलाने में कोई कमी शेष नहीं रखी। यह मोदीजी की नीतियों का ही परिणाम है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक एवं मुखिया चुनाव में पराजित हो गए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को पराजित किया। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के तरविंदर सिंह ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पराजित किया। इसके अतिरिक्त उनकी पार्टी के कई दिग्गजों को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा है।

वह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनता को भाजपा का सुशासन लुभा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात जनता को अनेक आश्वासन हुए घोषणा की थी कि उनकी सरकार जन कल्याण के कार्य करेगी एवं अन्तयोदय के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सुशासन राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि हमारा मंत्र, उद्देश्य व सिद्धांत नागरिकों को प्राथमिकता देने का है। मेरा सपना सरकार को लोगों के समीप लाने का है, जिससे वे प्रशासनिक प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन सकें। सरकारी कामकाज की प्रक्रिया को आसान कर सुशासन सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां के नागरिक शासन का भाग बनने के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी होना बहुत महत्वपूर्ण घटक है।

मोदीजी अन्तयोदय के मूल तत्वों के साथ निरंतर अग्रसर हैं, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

वास्तव में मोदीजी अन्तयोदय के मूल तत्वों के साथ निरंतर अग्रसर हैं, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। मोदी सरकार ने विकास का नारा दिया तथा विकास को ही प्राथमिकता दी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश के सभी वर्गों के लिए बिना किसी पक्षपात के कार्य किया है, उससे जनता के मध्य एक सकारात्मक संदेश गया है।

बेघर लोगों के लिए ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ आवासों का निर्माण करवाया गया। उल्लेखनीय यह है कि इन आवासों में से लगभग 70 प्रतिशत में महिलाओं का नाम हैं। महिलाओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त

6.5 करोड़ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार देशभर के 4335 कस्बों एवं ग्रामों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई गई। इससे महिलाओं में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा।

महिलाओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उन्हें चूल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। जिन क्षेत्रों में जल संकट था, वहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8.67 करोड़ घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 69 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में गैर–कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को दस लाख रुपये तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

मोदी सरकार ने कृषकों के कल्याण के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। देशभर के 11.39 करोड़ छोटे कृषकों को प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही 37.59 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट होने पर सरकार द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 1.37 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए अनेक पग उठाए, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सका। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से जनवरी 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने अभियान चलाया। लगभग 4.78 करोड़ नए सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता ली। स्टार्ट अप इंडिया के अंतर्गत 10.1 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में 60 लाख रोजगार सृजन करने की योजना बना रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विगत दो दशकों में आईटीआई की संख्या 11847 से बढ़ाकर 14955 की गई। देश में 390 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जनकल्याणकारी कार्य किए हैं। इससे पूर्व देश में एम्स की संख्या केवल आठ थी, जबकि आज 23 एम्स हैं। चिकत्सीय महाविद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई गई। पूर्व में 641 चिकित्सीय महाविद्यालय थे, जबकि अब इनकी संख्या 1341 है। इसके अतिरिक चिकित्सीय सीटों की संख्या 82466 से बढ़ाकर 152129 कर दी गई, जिससे कि अधिक छात्र प्रवेश ले सकें। इसके अतिरिक टीकारण अभियान चलाकर 220 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान विदेशों से भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इस दौरान लोगों को निःशुल्क राशन वितरण भी सुनिश्चित किया गया। आज भी देश के लगभग 80 लोगों को प्रति माह पांच किलो अन्न निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

परिवहन एवं यातायात के साधनों का भी विकास किया गया। सरकार द्वारा 13 वंदे भारत रेलें प्रारंभ की गई हैं। आगामी तीन वर्षों में 400 स्वदेश निर्मित ट्रेनें इसमें सम्मिलित करने का कार्य चल रहा है। मोदी के शासनकाल में देश ने लगभग सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। इनमें प्रमुख रूप से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक को अवैध घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना आदि सम्मिलित हैं। भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय–समय पर दोहराया है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी प्रयास का परिणाम है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विगत दो दशकों में आईटीआई की संख्या 11847 से बढ़ाकर 14955 की गई। देश में 390 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां तीव्र गति से विकास कार्य हो रहे हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश के उदाहरण सबके सामने हैं। इसलिए दिल्ली की जनता से भी डबल इंजन सरकार की अभिलाषा में भाजपा को अपना समर्थन दिया है। अब वह दिन दूर नहीं है, जब दिल्ली में भी गुजरात एवं उत्तर प्रदेश की भांति विकास कार्य होंगे।

निराधार प्रतिपक्षी राग, बदलता संविधान

हृदयनारायण दीक्षित

भारत में संविधान की सत्ता है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति निष्ठावान है। लेकिन कुछ समय से बहस चली है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव में भारी बहुमत पाकर संविधान बदल देंगे। बहस व्यर्थ है। संविधान साधारण अभिलेख नहीं है। जड़ नहीं गतिशील संस्था है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में संशोधन होते रहते हैं। अब तक लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में ही संविधान संशोधन के स्पष्ट प्रावधान हैं। संविधान बदलने और संशोधन करने में मूलभूत अंतर है। संविधान संशोधन विषयक प्रावधान (अनुच्छेद 368—मसौदा संविधान अनुच्छेद 304) पर संविधान सभा में बहस चली थी। बहस में हिस्सा लेते हुए एच. वी. कामथ ने कहा था, "संशोधन आखिरकार क्या है? संशोधन का अर्थ हो सकता है संविधान में कुछ परिवर्तन। उसमें कुछ जोड़ना या उसका निरसन।" लेकिन यहां संशोधन को लेकर कोई बहस ही नहीं। संविधान बदलने या खत्म करने की हास्यास्पद बयानबाजी है।

संविधान निर्माता संशोधन की आवश्यकता के प्रति सजग थे। सभा में पी. एस. देशमुख ने कहा था कि, "भविष्य में कुछ समय तक संविधान में तमाम परिवर्तन करने आवश्यक होंगे। इसलिए संविधान संशोधन आसान बनाना जरूरी है।" बृजेश्वर प्रसाद ने कहा कि, "किसी संविधान की अपरिवर्तनशीलता के कारण नई चीजें नहीं आ सकती। परिवर्तन रुक जाता है।" सभा में अनेक सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। डॉ. आम्बेडकर ने सभी सदस्यों के उत्तर दिए। कहा कि, "कनाडा के संविधान (1867) में संविधान संशोधन का कोई उपबंध नहीं है। आयरिश संविधान में, "दोनों सदन सामान्य बहुमत से संविधान के किसी भाग को संशोधित कर सकते हैं।" शर्त है कि सदनों के विनिश्चय को जनता का बहुमत अनुमोदित करे। स्विस संविधान में विधानमण्डल संशोधन विधेयक पारित कर सकता है। लेकिन जनता के अनुसमर्थन की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी जनता का बहुमत आवश्यक है।" उन्होंने अनेक उदाहरण दिए। भारत में संशोधन की शक्ति विधायिका में निहित है। उन्होंने संविधान सभा में विचाराधीन संशोधन विधेयक का विवेचन किया कि, "हम संविधान संशोधन को तीन श्रेणियां में बांटते हैं। एक श्रेणी में संसद का साधारण बहुमत पर्याप्त है। दूसरी श्रेणी के संशोधन में दो तिहाई बहुमत आवश्यक है। तीसरी श्रेणी में देश की आधे से अधिक विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है।" यहाँ संशोधन की पूरी प्रक्रिया औचित्यपूर्ण है।

कई सदस्यों ने सभा में संशोधन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। तर्क यह था कि कभी आम जनता राजनैतिक प्रणाली को बदलने की मांग कर सकती है इसलिए परिवर्तन आसान होना चाहिए। जन असंतोष के प्रकट करने का मार्ग भी होना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, "जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वह व्यस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में दो तिहाई बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह मान लेना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है।" उच्चतम न्यायालय ने स्थापना दी थी कि हमारे संविधान का कोई भाग ऐसा नहीं है जिसका संशोधन नहीं हो सकता। गोलकनाथ के चर्चित मुकदमे में 11 जजों की विशेष न्यायपीठ ने 6 न्यायाधीशों के बहुमत से पूर्व विनिश्चय को उलट दिया था और कहा था कि, "यद्यपि अनुच्छेद 368 में कोई अलग अपवाद नहीं है। लेकिन मूल अधिकारों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया के अधीन नहीं हो सकते। यदि ऐसे किसी

अधिकार का संशोधन करना है तो नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी।"

गोलकनाथ फैसले के बाद केशवानंद वाद का चर्चित फैसला आया। गोलकनाथ के वाद के समय से ही प्रश्न उठाया जा रहा था कि, "क्या मौलिक अधिकारों (भाग–3) के बाहर भी संविधान का कोई उपबंध है जो संशोधन की प्रक्रिया से मुक्त है?" केशवानंद के मुकदमे में बहुमत ने गोलकनाथ के मत को उलट दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन मूल अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता। एक अन्य बड़ी बात भी न्यायालय ने कही है कि संविधान के कुछ आधारिक लक्षण हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि संविधान संशोधन अधिनियम संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन के लिए है तो न्यायालय उसे शक्तिवाह्य के आधार पर शून्य घोषित करने का अधिकारी होगा। न्यायालय ने भारत की सम्प्रभुता, अखण्डता, परिसंघीय प्रणाली, न्यायायिक पुर्नविलोकन, संसदीय प्रणाली आदि अनेक विषयों को संविधान के आधारिक लक्षण बताए। इस तरह संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी कठिन हो गई है।

इंडिया गठबंधन संविधान बदलने और खत्म करने की निराधार कल्पना बार–बार दोहरा रहा है। संविधान में आपातकाल के लिए देश की आतंरिक अशांति को आधार बताया गया है। श्रीमती गाँधी ही आतंरिक अशांति से पीड़ित थी। देश नहीं। उन्होंने आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352) का दुरूपयोग किया। इंडिया गठबंधन को आपातकाल 1975–77 के समय पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का अध्ययन करना चाहिए। संविधान के विद्वान डॉक्टर डी॰डी॰ बसु ने ठीक लिखा है कि, "42वां संशोधन एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण ही था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में भी संशोधन हुए। 53 अनुच्छेद एक साथ बदले गए। सातवीं अनुसूची में भी परिवर्तन किए गए। 1949 के संविधान में सम्मिलित महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को बदल दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करने के आधार पर उसकी संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए संघ और राज्यों के कानून में भेद किया गया। यह उपबंध किया गया कि कोई उच्च न्यायालय किसी केन्द्रीय विधि या जिसमें ऐसी विधि के अंतर्गत अधीनस्थ विधान भी सम्मिलित हैं, संविधान विरुद्ध होने के आधार पर अविधि मान्य नहीं कर सकेगा।"

42वाँ संशोधन न्यायपालिका की शक्ति को घटाने वाला था और मौलिक अधिकारों की भी। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता (अनुच्छेद 32) में किसी राज्य विधि को असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा। संविधान संशोधन अधिनियमों के न्यायिक पुर्नविलोकन के अधिकार का भी संशोधन हुआ। उपबंध किया गया कि जिस विधि को संविधान संशोधन विधि बताया जाएगा, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 37) किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन यह उपबंध किया गया कि किसी निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने वाली विधि को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन से मुक्त रखा जाएगा। यह मूल संविधान के ठीक उल्टा है। देश को संविधान का अपमान याद रखना चाहिए।

श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान और उसकी आत्मा को ही कुचल दिया था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आई। जनसंघ जनता पार्टी का मुख्य घटक था। नई सरकार ने 43वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से न्यायायिक पुर्नविलोकन के न्यायपालिका के अधिकार की बहाली की। सभी जनविरोधी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। संविधान के प्रति भारतीय जन गण मन की निष्ठा है। संविधान बदलने या पूरा संविधान ही खारिज करने और तानाशाही लाने जैसे आरोप हास्यास्पद हैं। भारतीय संविधान के इतिहास में संविधान के साथ छेड़खानी का निन्दनीय कृत्य दूसरा नहीं मिलता। वे संविधान बदलने या हटाने की बात उठाकर आपातकाल की संवैधानिक त्रासदी याद दिला रहे हैं। इस दृष्टि से उनका यह कृत्य उपयोगी है। आपातकाल संवैधानिक त्रासदी है। आपातकाल की तानाशाही अत्याचार और संविधान को तहस–नहस करने के कृत्यों का पाठ और पुर्नपाठ जरूरी है।

नरेंद्र मोदी की गारंटी 'सबका विकास'

मीना चौबे

2025 का बजट भारत के लिए न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासशील दृष्टिकोण और उनके नेतृत्व में देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने वाला भी साबित हो सकता है। इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई अहम निर्णय और योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए। उनके नेतृत्व में सरकार ने "आत्मनिर्भर भारत" अभियान के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, और मेक इन इंडिया जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। 2025 के बजट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

जिसमे प्रमुख कृषि क्षेत्र में सुधार और समर्थन को देख सकते है जैसा कि हमेशा से मोदी सरकार का फोकस रहा है। 2025 के बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, कृषि कर्ज़ माफी और MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाने की घोषणाएं की हैं। किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नए रास्ते खोले गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त किया जा सके।

वैसे ही रोजगार सृजन और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मोदी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया है, ताकि उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं, और 5G नेटवर्क का विस्तार इसके प्रमुख हिस्से हैं।

वैसे ही स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री जी नें पहले ही कई कदम उठाए हैं, और बजट में भी इस दिशा में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए धन आवंटित किया गया है। इसके साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, नई पाठ्यचर्या, और विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप के प्रावधान किए गए हैं।

जैसा कि हम सब जानते कि किसी देश की आधारभूत संरचना का विकास से देश के बिकास को रफ्तार मिलती है तभी तो मोदी सरकार नें आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बजट में भारी निवेश का प्रस्ताव रखा है, मोदी सरकार ने सड़क, रेल, और हवाई मार्गों का विस्तार करने, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करने और जल संसाधन प्रबंधन को सुधारने की योजना बनाई है।

साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान है, और यह 2025 के बजट में भी स्पष्ट दिखाई देता है। सरकार ने सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, और शहरी जल निकासी प्रणाली पर जोर दिया है। मोदी सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का संकल्प लिया है।

नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने कार्यकाल के दौरान यह वादा किया है कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए विकास और समृद्धि सुनिश्चित करेगी। 2025 के बजट में प्रधानमंत्री ने फिर से इस वादे को पूरा करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। उनके द्वारा उठाए गए कदमों में विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए योजनाओं का विस्तार किया गया है। **"सबका साथ, सबका विकास"** का मोदी का मंत्र इस बजट में पूरी तरह से परिलक्षित होता है। उनका उद्देश्य है कि सरकार के सभी फैसले समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए हों, और हर भारतीय को समृद्धि का लाभ मिले। 2025 का बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से अपने वादे को पूरा करने की दिशा में कई योजनाएं और सुधार प्रस्तुत किए हैं। यह बजट न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए समृद्धि और विकास का प्रतीक बनेगा। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का समाज के हर वर्ग के लिए समृद्धि का वादा है।

अवैध नागरिकों की वापसी हर देश की जिम्मेदारी

एस. जयशंकर

नया नहीं है अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजा जाना, एस जयशंकर ने संसद में बताया कब कितने भेजे गए: कहा– दुर्व्यवहार न हो यह सुनिश्चित करने का सरकार कर रही प्रयास जयशंकर ने कहा कि अमेरिका की ओर निर्वासन की प्रक्रिया और क्रियान्वयन आव्रजन तथा सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) द्वारा किया जाता है। ICE द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों में निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) है, जिसमें प्रतिबंधों के उपयोग (हथकड़ी और बेड़ी पहनाने) का प्रावधान है। हालाँकि, महिलाओं और बच्चों को इस तरह से नहीं बाँधा जाता है।

अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा 104 भारतीयों को

वापस भेजने के बाद सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसको लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार (6फरवरी 2025) को बयान दिया और कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने साल 2009 से लेकर 2025 तक आँकड़े दिए और बताया कि कब–कब अमेरिका ने भारतीयों को वापस भेजा है।

राज्य सभा में जयशंकर ने कहा, "हम अमेरिकी सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क कर रहे हैं कि निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। साथ ही, सदन इस बात की सराहना करेगा कि हमारा ध्यान अवैध आव्रजन उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर होना चाहिए। निर्वासितों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ एजेंटों और ऐसी एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक, निवारक और अनुकरणीय कार्रवाई करेंगी।"

जयशंकर ने कहा कि सभी देशों की ज़िम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। अपने अवैध नागरिकों को वापस लेना हर देश की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों को निर्वासित करने की प्रक्रिया नई नहीं है। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है।

उन्होंने बताया कि अमेरिका से साल 2009 में 734, साल 2010 में 799, साल 2011 में 597, साल 2012 में 530, साल 2013 में 550, साल 2014 में 591, साल 2015 में 708, साल 2016 में 1303, साल 2017 में 1024, साल 2018 में 1180, साल 2019 में 2042, साल 2020 में 1889, साल 2021 में 805, साल 2022 में 862, साल 2023 में 670, साल 2024 में 1368 और साल 2025 में 104 लोग भारत भेजे गए।

जयशंकर ने कहा कि अमेरिका की ओर निर्वासन की प्रक्रिया और क्रियान्वयन आव्रजन तथा सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) द्वारा किया जाता है। ICE द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों में निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) है, जिसमें प्रतिबंधों के उपयोग (हथकड़ी और बेड़ी पहनाने) का प्रावधान है। हालाँकि, महिलाओं और बच्चों को इस तरह से नहीं बाँधा जाता है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि सभी देशों के लिए यह जरूरी है कि वे अवैध प्रवास को हतोत्साहित करें और कानूनी तरीकों से लोगों की आवाजाही को बढ़ावा दें।

यह सभी देशों की ज़िम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो वह उन्हें वापस ले।

'महाकुंभ' विकृत राजनीति?

मृत्युंजय दीक्षित

प्रयागराज में 144 वर्षों के पश्चात होने वाला महाकुंभ अपने आयोजन के आरंभ के साथ ही सनातन विराधी शक्तियों के निशाने पर है, चाहे वह महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें आवंटित करने का प्रकरण रहा हो या फिर व्यवस्थाओं को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव की बयानबाजी। कुम्भ को लेकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो रही बयानबाजी के पीछे का प्रमुख कारण सपा नेता का यह डर था कि कुम्भ का सफल आयोजन मुख्यमंत्री के पक्ष में एक लहर उत्पन्न कर देगा और 2027 की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जायेगा।

पौष पूर्णिमा के साथ 13 जनवरी को पूर्ण भव्यता के साथ आरम्भ हुआ कुम्भ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की दिन दूनी रात चौगुनी उमड़ती भीड़ और व्यस्थाओं के प्रति उसके संतोष से सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। हर व्यक्ति कुम्भ की बढ़ चला। हर ओर सनातन के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनके सक्षम प्रशासन की चर्चा होने लगी। इसके साथ साथ सनातन विरोधियों तथा मोदी योगी के राजनैतिक विरोधियों की ईर्ष्या भी परवान चढ़ने लगी। विरोधी महाकुंभ और उसकी व्यवस्थाओं को बदनाम करने के लिए प्रतिदिन कोई न कोई अफवाह फैलाकर महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह की कमी करने का प्रयास करने लगे।

सपा मुखिया ने महाकुंभ की छवि खराब करने को अपना राजनैतिक लक्ष्य बना लिया है। पार्टी ने महाकुंभ में हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए रामभक्तों का नरसंहार करने वाले उनके पिता मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगवाई और अपने चाचा के अस्थि विसर्जन के समय उनके गंगा स्नान को कुम्भ से जोड़कर प्रसारित किया। हिंदू समाज का दबाव बढ़ने पर अखिलेश यादव गणतंत्र दिवस के दिन महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए पहुंच गये थे और अपने पिता को महान संत कह डाला। सपा मुखिया अखिलेश यादव उस समय महाकुंभ पहुंचे जब मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। स्पष्ट है कि सपा मुखिया अखिलेष यादव अपनी विकृत राजनीति का संदेश देने ही प्रयागराज गये थे।

श्रद्धालुओं के भारी दबाव के कारण संगम तट पर दुखद भगदड़ की स्थिति बनी और 30 श्रद्धालु मौन हो गये। प्रशासन की सतर्कता से स्थिति शीघ्र ही नियंत्रण में आ गई अन्यथा यह त्रासदी और भयावह हो सकती थी। अधिकारियों ने जिस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाईं तथा संगम घाट पर स्नान अआरम्भ कराया वह अत्यंत प्रशंसनीय है। व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के साथ ही घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग भी बना दिया गया है क्योंकि घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान किसी षड्यंत्र का संकेत दे रहे हैं।

इस दुर्घटना के बाद न तो सनातनी श्रद्धालुओं की निष्ठा पर कोई असर पड़ा और न ही योगी जी की कर्तव्यनिष्ठा पर उनके विश्वास को ठेस पहुंची किन्तु सपा मुखिया अखिलेश

यादव और अन्य विरोधियों को राजनैतिक रोटियां सेंकने का अवसर अवश्य मिल गया। बिल्ली के भाग्य से छींका टूट ही गया। विपक्षी इस दुर्घटना में अपनी राजनीति का आसान रास्ता खोज रहे हैं। इन्हें अपना इतिहास याद करना चाहिए। जब नेहरू और सपा सरकार में मची थी भगदड़ – 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का प्रथम पूर्णकुंभ तत्कालीन इलाहाबाद में 1954 में लगा था। उस वर्ष मौनी अमावस्या 3 फरवरी को पड़ी थी। तब बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ और फिसलन थी। सुबह लगभग आठ से नौ बजे के मध्य सूचना आई कि प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू स्नान करने के लिए आ रहे हैं, भीड़ उन्हें देखने के लिए टूट पड़ी और

भगदड़ मच गई। जिसके कारण कम से कम 1000 लोग मारे गये और अनेकानेक घायल हुए तथा कई लापता हो गये। जो कांग्रेसी आज महकुंभ की दुर्घटना पर सोशल मीडिया में जहर उगल रहे हैं उन्हें अपने कर्म व इतिहास याद रखने चाहिए। जो कांगेस पार्टी आज योगी सरकार से इस्तीफा मांग रही है उस समय राज्य में उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि यहां पर कोई दुर्घटना घटी ही नहीं है। उस समय के एक खोजी पत्रकार एन एन मुखर्जी जो उस समय वहां पर उपस्थित थे उन्होंने कुंभ की कुछ तस्वीरें खींच ली थी जो छायाकृति नामक एक हिंदी पत्रिका में प्रकाशित हुयी थीं और सच सामने आया था। उस समय दबाव बढ़ने पर सरकार की ओर से शर्मनाक बयान दिया गया था कि वहां पर कुछ भिखारी ही मरे हैं। उस समय राजभवन में सरकारी पार्टियों का दौर चल रहा था, जिसकी तस्वीरें तत्कालीन समाचार नहीं नहीं उपलब्ध हो सका था। अखिलेश यादव ने कुंभ की जिम्मेदारी अपने मुस्लिम मंत्री आजम खां को दी थी। 10 फरवरी 2013, मौनी अमावस्या का दिन था लगभग लोग गंगा की पवित्र डुबकी लगाकर वापस जा रहे थे तभी शाम को प्रयागराज जंक्शन पर चीख पुकार मच उठी।

रेल का प्लेटर्म बदलने की घोषणा हो जाने के कारण रेलवे पुल पर बहुत भीड़ हो गई थी और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भगदड़ से 36 लोगो की जानें चली गई। उस समय रेलवे कुंभ वार्ड में ताला लगा हुआ था और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। रुई और पट्टी को छोड़कर कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी। आज की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीड़ित परिवारों को 25—25 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है जबकि अखिलेश यादव ने तो मात्र एक लाख रुपये की ही सहायता राशि दी थी और पीड़ितों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था तक नहीं की थी। योगी सरकार पर

पत्रों में प्रकाशित हुई थी। उपन्यासकार समरेश बसु ने "अमृत कुंभ की खोज" उपन्यास में नेहरु जी के कारन कुम्भ में हुयी इस दुर्घटना का हृदयविदारक विवरण लिखा था और यह अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस समय के नेहरू भक्तों का कहना था कि घटना के समय नेहरू जी वहां पर नहीं थे किंतु बाद में उन्होंने ही इस बात से संसद में पर्दा उठाया था कि वह दुर्घटना के समय वहां पर मौजूद थे और उनका यह बयान आज भी संसद के लाइब्रेरी कक्ष में मौजूद है।

इसके विपरीत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया गया है, स्वयं मुख्यमंत्री दिन रात वाररूम में स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और उस समय कुम्भ में मची भगदड़ में मृतकों को कफन तक सवाल उठाने वालों को अपना इतिहास याद रखना चाहिए। अभी तक महाकुंभ में हुए किसी भी हादसे की जांच, किसी भी सरकार ने नहीं करवायी है यह योगी सरकार ही है जो महाकुंभ हादसे की दो स्तरीय जांच करवाने जा रही है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

यह बहुत ही गर्व की बात है कि महाकुंभ में दुखद दुर्घटना के बाद भी सनातन हिंदू समाज का उत्साह कम नहीं हुआ है अपितु वहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब लगातर उमड़ रहा है और वे उसी भक्ति, श्रद्धा और आस्था से पवित्र दुबकी लगा रहे हैं। जिस प्रकार से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अनेक देशों के प्रतिनिधी निरन्तर डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के ऑकड़े निरन्तर अपने रिकार्ड को तोड़ते जा रहे हैं। सांस्कृतिक कुम्भ धरा के लिए लोक कल्याणकारी होगा।

भगवामय दिल्ली के राजनीतिक निहितार्थ!

शिव भूषण त्रिपाठी

भारतीय लोकतान्त्रिक राजनीति में ऐसे कई चुनावी परिणाम आये है जिन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि हमारे राष्ट्र की चुनावी पद्धति कितनी मजबूत एवं जनहित हेतु प्रतिबद्ध है। इसका हालिया उदाहरण है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम।

27 वर्षों के राजनीतिक वनवास झेलने वाले भगवा खेमे का विजय रथ राजधानी पहुँच चुका है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में भाजपा 48 सीटों के एक तिहाई बहुमत के साथ मजबूत वापसी की है, और अब तक के रिकार्ड सीटों से सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ही समेट कर मजबूत शिकस्त दी है। सामाजिक आंदोलन की उपज आम आदमी के रूप में दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करने वाले मफलरधारी केजरीवाल अपने ही गफलत में फस गए और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जैसे नेता को तीन बार हराने वाले केजरीवाल इस लहर में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया साहित कई मंत्री भी बुरी तरह चुनाव हार गए। वहीं कांग्रेस अपने परम्परागत परिणाम को जारी रखा है और फिर एक बार उसकी स्थिति न पाने की खुशी और न खोने का गम जैसा रहा। अर्थात् फिर उसका खाता नहीं खुल पाया। यदि एक बार इस राजनीतिक कलखंड को देखें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जायेगा।

देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का गठन 20 वीं सदी के अंतिम दशक वर्ष 1993 में हुआ, उस समय राजधानी के प्रथम चुनाव परिणाम का स्पष्ट संदेश भाजपा के साथ था और 70 सीटों में से 49 सीटें पाकर दिल्ली की पूर्ण बहुमत की सरकार में मदन लाल खुराना राजधानी के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस मात्र 14 सीट पर ही सिमट गई। मदन लाल खुराना दिल्ली के संरचनात्मक विकास हेतु प्रतिबद्ध रहें किन्तु उनका कार्यकाल बहुत लम्बा नहीं रहा और उस समय के चर्चित हवाला कांड में नाम आने भर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तथा बेदाग साबित नहीं हो जाने तक राजनीति से मुक्त रहने का फैसला किया।

तत्पश्चात 1996 में भाजपा के अगले मुख्यमंत्री साहिबसिंह बर्मा बनाए गए और और वह भी दिल्ली को सजाने सवारने में लग गए किन्तु भाजपा संगठन एवं सरकार में उस समय कठिन निर्णय का समय आया जब मदन लाल खुराना बेदाग साबित हुए और वह पुनः मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर किये लेकिन साहिबसिंह वर्मा हटने को तैयार नहीं थे। तब भाजपा ने इन दोनों के विवाद को सीमित करते हुए बीच का रास्ता निकाल कर अक्टूबर 1998 में सुषमा स्वराज के रूप में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री दिया। सुषमा जी ऐसे अपने कार्यपद्धति एवं सरकार की नीतियों को लेकर प्रखर थी, किन्तु चंद महीनो में ही विधानसभा चुनाव आ गए और दिल्ली की जनता को बढ़ती महंगाई और 5 साल में तीन मुख्यमंत्री यह रास नहीं आया, और इतने सारे अच्छे कामों के बावजूद भी भाजपा बुरी तरह चुनाव हार गई, और भाजपा को 15 सीटे मिली व कांग्रेस 52 सीटों के साथ एक तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाई और 3 दिसंबर 1998 को शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इस तरह उनके कार्यो को राजधानी ने सिर माथे लिया जिससे कांग्रेस लगातार डेढ़ दशक तक (1998 से 2013) राष्ट्रीय राजधानी के सत्ता पर काबिज रही।

दिल्ली में लम्बे समय तक कांग्रेस का सरकार में बने रहने का मुख्य कारण था शीला दीक्षित जी के समय फ्लाईओवर और मेट्रोकनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों एवं स्पष्ट नीति थी। किन्तु 2010 मे हुए कॉमनवेल्थ घोटाले ने दिल्ली के लोगों का कांग्रेस से मोहभंग करना प्रारम्भ कर दिया तथा कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरती गई, इधर 2011 आते ही देश की राजधानी एक नए सामाजिक आंदोलन से जागृत हो महाराष्ट्र के वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व मे जन लोकपाल विधेयक की मांग हेतु भ्रष्टाचार मुक्त भारत के गंगन चुंबी नारों से गूंजने लगी जिसमें छोटा – बड़ा, विद्यार्थी, कर्मचारी, अधिकारी, अधिवक्ता और कवि साहित्यकार अथवा समाज का हर वर्ग साथ आया तथा सब एक साथ खड़े होकर कांग्रेस के खिलाफ मुखर हुए, यह आंदोलन पूर्णतया राजनीति से मुक्त था और लग भी रहा था कि राजधानी की यह ललकार

सम्पूर्ण देश में इसी स्वर में जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्ति का सपना साकार होगा किन्तु देश काल वातावरण ने इस आंदोलन को भी अपने आगोश में ले ही लिया और कुछ महत्वाकांक्षी लोग जिनके मन में तो सत्ता की चाह थी अर्थात् वह अपनी राजनीतिक क्षुधा की व्याकुलता में भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 2012 को राजनीतिक दल की स्थापना किये जिसका नाम दिए आम आदमी पार्टी। इसमे कवि कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा आशुतोष कुमार जैसे लोग अलग अलग क्षेत्र के महनीय लोग थे।

इस पार्टी के मुखिया के रूप में अरविन्द केजरीवाल जो कि प्रशासनिक सेवा से आये थे, उन्होंने आम आदमी की तरह स्वच्छ, साफ – सुथरी एवं ईमानदार राजनीति का संकल्प लेते हुए 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिजली पानी स्वास्थ्य एवं शिक्षा को मुद्दा बनाया, जिससे दिल्ली की राजनीतिक दिशा और दशा बदल गई तथा कांग्रेस पर रोपित भ्रष्टाचार एवं एंटी इनकम्बेसी से परेशान होकर दिल्ली की जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। हालांकि भाजपा अपने मतप्रतिशत में बढ़ोत्तरी करते हुए 31 सीटे तो पाई किन्तु 5 सीटों की कमी के कारण सरकार ना बना सकी उधर नई नवेली आम आदमी पार्टी ने 28 सीट पाकर 8 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर सत्ता को प्राप्त करने की चाह को पूर्ण किया, जिसके खिलाफ इस दल एवं विचार का प्रकाट्य हुआ था। इस प्रकार दिल्ली में शुरू हुई केजरीवाल की आम पारी खास बनने के लिए आतुर थी, जो दिखने में तो आम थी लेकिन आम उसी तरह थी जैसे गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है, क्योंकि चुनाव में केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाकर कहते थे कि न बंगला लूंगा, न गाड़ी और न ही कभी कांग्रेस के साथ जाऊंगा बल्कि शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा किन्तु मौका पाते ही सरकार बना मुख्यमंत्री बन गए।

किन्तु प्रतिकूल विचारों की ये अनुकूलता बहुत दिन तक टिक नहीं पाई और 47 दिन बाद ही केजरीवाल इस्तीफा देकर सबको चौका दिए और दिल्ली में कुछ दिन तक राष्ट्रपति शासन लग गया तथा एक वर्ष बाद फरवरी 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में अरविन्द केजरीवाल ने 70 में से 67 सीट पाकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार 2020 में भी मुफ्त पानी बिजली की घोषणा कर उन्होंने भारतीय राजनीति ने रेवड़ी पद्धति की नींव मजबूत की और 70 में से 62 सीट पाकर सरकार बनाई। किन्तु जैसे जैसे समय बीतता गया वह एक के बाद एक आरोपों से घिरते रहें, हालांकि आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी उसकी सरकार बन गई किन्तु उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे और वह लगातार कभी शराबनीति घोटाला, शीशमहल और अन्य आरोपों पर घिरते रहें।

इस विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा दिल्ली के कचरे का निस्तारण, टूटी सड़के, सीवेज का पानी, यमुना प्रदूषण और प्रदूशित हवा थी, जिसने जनता के मन मस्तिष्क पर मुफ्त की रेवड़ियों से गहरा प्रभाव डाला और भाजपा इसे भुनाने में सफल रही ऐसे चुनावी रेवड़ियों को रोकना अब किसी भी राजनीतिक दल के सामर्थ्य में नहीं है बल्कि इसके स्वरूप में वृद्धि ही होती जा रही है उधर केजरीवाल 2100 देने का वादा किये थे तो भाजपा 2500 कहकर सरकार में आयी है अतः यह रेवड़ी संस्कृति निश्चित ही भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है किन्तु इसका उन्मूलन सामाजिक सहभागिता से ही सम्भव है क्योंकि राजनीतिक दल तो इससे अपना वोटबैंक मजबूत करते है। अतः इस जीत में भाजपा के स्थानीय संगठन और उसके मातृसंगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सफल संयोजन के अनुरूप दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच एवं पूर्वांचली वोटो पर पकड़ ही इस जीत के महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। उधर चुनावी मंचो पर केजरीवाल का हरियाणा के लोगो पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप भी आप के लिए घातक सिद्ध हुआ। केंद्र सरकार द्वारा 1 फ़रवरी को आये बजट में मध्यवर्गीय करदाताओं हेतु विशेष छूट एवं आठवें वेतन अयोग का सकारात्मक परिणाम भी मतदाताओं को आकर्षित किया तथा बार बार प्रधानमंत्री का सेवा करने का आग्रह भी दिल्ली ने दिल से स्वीकार किया ।

अतः भाजपा की यह जीत सिर्फ आप ही नहीं अपितु इंडी गठबंधन को भी सोचने एवं समीक्षा करने के लिए विवश कर दिया है क्योंकि चुनाव से पहले ही कॉंग्रेस अलग थलग दिखी अब परिणाम के बाद और दरार पड़ सकती है क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और शिवसेना उद्धव ग्रुप के संजय राउत के बयान इस बात की ओर संकेत करते है कि यदि कांग्रेस और आप अलग चुनाव न लड़ते तो शायद स्थिति कुछ और होती। खैर दिल्ली की जनता ने इस बार डबल इंजन की सरकार पर विश्वास कर ही लिया है, अब चुनी हुई सरकार दिल्ली के सर्वांगीण एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए जनहित मुद्दे को ध्यान में रखें।

भाजपा की यह जीत सिर्फ आप ही नहीं अपितु इंडी गठबंधन को भी सोचने एवं समीक्षा करने के लिए विवश कर दिया है क्योंकि चुनाव से पहले ही कॉंग्रेस अलग थलग दिखी अब परिणाम के बाद और दरार पड़ सकती है।

स्वर्णिम भारत का पर्याय है सांस्कृतिक विरासत

डॉ. शंकर सुवन सिंह

संविधान लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम/प्रसंग थी "स्वर्णिम भारत–विरासत और विकास"। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को चुना गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आजादी के बाद देश को चलाने के लिए डॉ भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया। जिसे लिखने में पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किये जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 ई. को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। गण और तंत्र। वैदिक काल में गण का शाब्दिक अर्थ था दल/समूह/लोक। तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है डोरा/सूत (रस्सी)। अर्थात ऐसी रस्सी/डोरा, जो लोगों के समूह को जोड़े। लोकतंत्र कहलाता है और यही गणतंत्र है। अतएव हम कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान को लागू किये जाने का द्योतक है। संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द बाद में भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा भारतीय आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। भारत में आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) के दौरान, इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के बयालीसवें संशोधन में कई बदलाव किए थे। इसी संशोधन के ज़रिए "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को "संप्रभु" और "लोकतांत्रिक" शब्दों के बीच जोड़ा गया और "राष्ट्र की एकता" शब्दों को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" में बदल दिया गया। भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। अतएव भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से स्वावलम्बन, स्वाभिमानता और समानता परिलक्षित होती है। स्वावलम्बिता, स्वाभिमानिता और समानता के मूल में स्वाधीनता वास करती है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, विचारों की स्वतन्त्रता, विश्वास की स्वतन्त्रता, आस्था और पूजा की स्वतन्त्रता स्वतंत्र भारत की पहचान है। अतएव हम कह सकते हैं कि अक्षुण्ण विरासत और विकास की सेतु पर खड़ा सविधान ही भारतीय गणतंत्र व्यवस्था की पहचान है। आत्मविश्वास का होना ही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। भगवद गीता में लिखा है नायं आत्मा बलहीनेन लभ्यः अर्थात यह आत्मा बलहीनो को नहीं प्राप्त होती है। आत्मबल ही आत्मविश्वास की जननी है। आत्मबल और आत्मनिर्भर शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बी होने को दर्शाता है। स्वावलम्बन जव जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलम्बी अवश्य होना चाहिए। रामराज्य की परिकल्पना मोहनदास करमचंद गांधी की दी हुई थी। गांधीजी ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति के पश्चात ग्राम स्वराज के रूप में रामराज्य की कल्पना की थी। आत्मनिर्भरता, रामराज्य की परिकल्पना पर आधारित है। आत्मनिर्भर भारत की नींव गांधी के रामराज्य पर टिकी थी। गाँधी जी का स्वराज्य, रामराज्य की परिकल्पना का आधार था। स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन–आवश्यकताओं तथा जन–आकांक्षाओं के अनुरूप हो। यही स्वराज्य रामराज्य कहलाया। स्वराज का तात्पर्य स्वतंत्रता से है। बिना आत्मनिर्भर हुए स्वतंत्र नहीं हुआ जा सकता है। आत्मनिर्भरता या स्वावलम्बिता स्वतंत्र होने की एक कड़ी है। जब हम स्वतंत्र होंगे तभी हम स्वाभिमानी होंगे अर्थात स्वाभिमानिता के लिए स्वाधीनता जरुरी है। हिन्दुस्तान को गांधी का रामराज्य चाहिए। राम राज्य भगवान् राम के पुरुषार्थ और शासन का द्योतक है। भगवान् राम सहिष्णुता के प्रतीक थे। राम सत्य के प्रतीक थे। तभी तो भगवान् राम ने रामराज्य

स्थापित किया था। आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है और वहीं दूसरी ओर विदेशी कम्पनियाँ और विदेशी सामान की हिन्दुस्तान में बाढ़ आ गई है। प्रत्येक संस्था का निजीकरण होता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ा है। यदि स्वावलम्बन, समानता और स्वाभिमान की बात करनी हो तो गांधी के रामराज्य की कल्पना करनी होगी। अतएव हम कह सकते हैं कि स्वतन्त्रता, गांधी के रामराज्य की परिकल्पना पर आधारित होनी चाहिए। सभी राजनैतिक पार्टियों को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों को आत्मसात करने की जरुरत है। वास्तव में भारत तभी स्वावलम्बी और स्वाभिमानी बन पाएगा। भारत को रामराज्य की परिकल्पना अपने पूर्वजों या पुरखों से विरासत में मिली हैं। रामराज्य की परिकल्पना रूपी विरासत को संजोकर रखने की जरुरत है। अयोध्या का राम मंदिर अपनी सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय उदाहरण है। भगवान् राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर को पुनर्जीवित करना ही अपनी विरासत को सम्हालने का एक अच्छा उदहारण है। किसी भी देश की विरासत उस देश के विकास की आधारशिला होती है। पुरखों से प्राप्त वस्तु, सम्पत्ति आदि को विरासत कहा जाता है। पूर्वजों द्वारा प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति आदि को ही विरासत कहा जाता है। विश्व में भारत अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वर्णिम स्थान रखता है। भारत विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं,और संस्कृतियों का देश रहा है। भारत में मुख्यतः निम्नलिखित विरासतें हैं:–1.सांस्कृतिक विरासत 2.प्राकृतिक विरासत 3. मिश्रित विरासत। सांस्कृतिक विरासत दो प्रकार की होती है– मूर्त संस्कृति और अमूर्त संस्कृति। सांस्कृतिक विरासत में मूर्त संस्कृति जैसे इमारतें, स्मारक, परिदृश्य, अभिलेखीय सामग्री, किताबें, कला के कार्य और कलाकृतियाँ आदि आते हैं। अमूर्त संस्कृति जैसे लोकगीत, परंपराएँ, भाषा और ज्ञान) और प्राकृतिक विरासत (सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण परिदृश्य और जैव विविधता सहित) शामिल हैं। मिश्रित विरासत स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल होते हैं। भारत में 43 यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थान शामिल हैं। भारत में यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) द्वारा अनुरक्षित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घटक शामिल हैं। इन धरोहर स्थलों से विदित होता है कि भारत ने विरासत में अपने पूर्वजों से और प्रकृति से स्वर्णिम धरोहर प्राप्त किये। भारत में रामायण (बाल्मीकि), महाभारत व भगवद गीता (वेद व्यास), मनु स्मृति (ऋषि मनु),अभिज्ञान शाकुंतलम (कालिदास), रामचरित मानस (तुलसीदास),आदि असंख्य ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों ने की। वेद, पुराण, उपनिषद और दर्शन आदि ये सभी भारतीय विरासत के अभिन्न अंग हैं। वेदों से ही चौथा वेद अथर्वेद आया। आज विश्व में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्णिम भारत की छवि को विश्व पटल पर रख चूका है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन से ही आज विश्व प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ही देन है जिसकी वजह से 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। भारत ऋषि मुनियों और देवताओं की भूमि रही है जहां राजा हरिश्चंद्र (सतयुग), भगवान् राम (त्रेता युग), भगवान् कृष्ण (द्वापर युग) आए। श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है, वहीं कुछ धर्मशास्त्रों में 24 अवतार भी बतलाए गए हैं. जिनमें से "दशावतार" (दस अवतार) प्रमुख हैं. गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन है. वे हैं– मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। भगवान् के ये सारे अवतार भारत भूमि को स्वर्णिम बनाते है। इन ऋषि मुनियों और देवताओं से विरासत के रूप में प्राप्त संस्कार भारत की संस्कृति को विश्व में स्वर्णिम या अद्वितीय बनाते हैं। यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) द्वारा वर्ष 2017 में कुम्भ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। जो भारत के लिए अपूर्व गर्व का दिन था। वर्ष 2025 में प्रयागराज जिले में 144 वर्षों बाद लगा महाकुम्भ – 2025 (धार्मिक समागम), सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय स्रोत है। इस बार महाकुंभ मेला 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला में आयोजित किया गया , जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। प्रयाग में तीन नदियों का संगम है– गंगा, यमुना और सरस्वती। महाकुम्भ के मुख्य स्नान पर्व पर किया गया स्नानअत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति देता है। कहते हैं इस समय किया गया स्नान मोक्ष दायनी होता है। महाकुम्भ के समय हिन्दू देवी देवता सभी किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। इस समय बड़े बड़े चमत्कारी साधू संत अपना प्रवास करते हैं। इनका आशीर्वाद मतलब देवताओं का आशीर्वाद होता है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में चार पवित्र स्थलों द् प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, और नासिक में आयोजित होता है। यह मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु–संत, और पर्यटक एकत्रित होते हैं। महाकुंभ की जड़ें हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में समुद्र मंथन से जुड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन चार स्थानों पर गिरीं, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए।

किसी भी राष्ट्र के विकास में संस्कृति एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाती है।किसी भी देश का विकास सांस्कृतिक विरासत के बिना संभव नहीं है। भारत की विरासत अक्षुण्ण है। इसको क्षीण नहीं किया जा सकता। भारत की विरासत ही उसके विकास की जननी है। अतएव हम कह सकते हैं कि अक्षुण्ण विरासत, स्वर्णिम भारत का प्रतिबिम्ब है।

मोदी पर जन-जन का विश्वास

दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'विजयोत्सव' मनाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व श्री ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दया शंकर सिंह की मौजूदगी में हुए विजयोत्सव में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया।

पार्टी के राज्यमुख्यालय पर हुए 'विजयोत्सव' में प्रदेश महामंत्री श्री गोविन्द नारायण शुक्ला, श्री राम प्रताप सिंह चौहान, श्रीमती अंजुला माहौर, श्री अमित वाल्मीकि, श्री शिवभूषण सिंह, श्री मनीष दीक्षित, श्री भारत दीक्षित, श्री अतुल अवस्थी, चौधरी श्री लक्ष्मण सिंह, श्री आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मिलित हुए।

प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया। दिल्ली विधानसभा में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पर जनता के विश्वास का परिणाम है। जनता ने माननीय मोदी जी की नेतृत्व में भाजपा की गरीब कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और संकल्पों पर भरोसा कर दिल्ली में भाजपा को जनादेश दिया है।

अयोध्या की महान जनता ने मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री चन्द्रभानु पासवान को भारी अंतर से विजयी बनाया है। समाजवादी पार्टी सहित समूचे विपक्ष का जो निगेटिव ऐजेण्डा था उस नकारात्मक ऐजेंडे को नकारने का काम जनता ने किया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के मामले में अभूतपूर्व ढंग से काम किया है। चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने घर–घर जाकर मोदी जी–योगी जी के नेतृत्व में केन्द्र व प्रदेश की एनडीए गठबंधन की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जन–जन के समक्ष रखा और सतत संपर्क व संवाद के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे। जिसका परिणाम मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को बड़े अंतर से विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यह सब की सब अब समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी है तो सुशासन है। भाजपा गरीबो के कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य की गांरटी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सच्ची जीत हुई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, झूठ, लूट, गुंडगर्दी, तुष्टिकरण तथा परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हार गए है। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली विजय की त्रिवेणी बह रही है, विपक्ष की राजनीति डूब रही है। दिल्ली की जीत, देश की जीत है। मिल्कीपुर की जीत, यूपी की जीत है। आज का दिन ऐतिहासिक है। दिल्ली की जनसुनामी, नकारात्मकता, झूठ और साजिशों की राजनीति को जनता का करारा जवाब है। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है और रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का विजय रथ बढ़ता जा रहा है। विपक्षियों का कोई भी षड्यंत्र और साजिश जनता के आशीर्वाद के आगे नहीं टिकेगी। उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव मंप पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए मतदाताओं का आभार जताते हुए अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के विश्वास की जीत है। देश की जनता लगातार विपक्ष की तुष्टिकरण, परिवारवाद तथा भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार कर भाजपा के विकास और सुशासन को अपना आशीर्वाद दे रही है।

'अंत्योदय' भारत के विश्वगुरु बनने का महामंत्र

सुरेन्द्र शर्मा

भारत के आधुनिक मनीषियों चिंतकों जिन्होंने भारत के स्व को पहचानकर भारतीयता के आधार पर भारत के स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न देखा जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता की और कहा बिना समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उद्धार हुए राष्ट्र का अपने बल पर खड़ा होना मुश्किल है"अंत्योदय से ही राष्ट्रोदय" संभव है का मंत्र देने वाले आज की भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणापुंज और जनसंघ के आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नियति ने 11 फरबरी 1968 को देश से छीन लिया पर उनके बताए मार्ग पर चलकर देश की नरेन्द्र मोदी जी सरकार एवं देश के 21 राज्यों की भाजपा सरकारें अपनी गरीब कल्याण की सैकड़ों योजनाओं से दीनदयाल जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार कर रही हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि मथुरा में नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। बचपन में एक ज्योतिषी ने इनकी जन्मकुंडली देख कर भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान विद्वान एवं विचारक बनेगा, एक अग्रणी राजनेता और निःस्वार्थ सेवाव्रती होगा मगर ये विवाह नहीं करेगा। बचपन में ही दीनदयाल जी को एक गहरा आघात सहना पड़ा जब सन 1934 में बीमारी के कारण उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गयी। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा वर्त्तमान राजस्थान के सीकर में प्राप्त की। विद्याध्ययन में उत्कृष्ट होने के कारण सीकर के तत्कालीन नरेश ने बालक दीनदयाल को एक स्वर्ण पदक, किताबों के लिए 250 रुपये और दस रुपये की मासिक छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया।

दीनदयाल जी ने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वह बीए. की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कानपुर आ गए जहां उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला लिया। अपने एक मित्र श्री बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से सन 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। उसी वर्ष उन्होंने बीए. की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद एमए. की पढ़ाई के लिए वो आगरा आ गए।

आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करते हुये उनका परिचय श्री नानाजी देशमुख और श्री भाउ जुगडे से हुआ।इसी समय दीनदयाल जी की बहन सुश्री रमादेवी बीमार पड़ गयीं और इलाज के लिए आगरा आ गयीं। मगर दुर्भाग्यवश उनकी भी मृत्यु हो गयी। दीनदयाल जी के लिए जीवन का यह दूसरा बड़ा आघात था। इसके कारण वह अपनी एमए. की परीक्षा नहीं दे सके और उनकी छात्रवृत्ति भी समाप्त हो गयी।

अपनी चाचीजी के कहने पर दीनदयाल जी एक सरकारी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में वो धोती और कुरता पहने हुए थे और अपने सर पर टोपी लगाए हुए थे। अन्य परीक्षार्थी पश्चिमी ढंग के सूट पहने हुए थे। मज़ाक में उनके साथियों ने उन्हें "पंडित जी" कह कर पुकारना शुरू कर दिया, आगे चलकर उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायी आदर और प्रेम से उन्हें इसी नाम से पुकारने वाले थे। इस परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

पंडित दीनदयाल जी इसके बाद बीटी. का कोर्स करने के लिए प्रयागराज आ गए और यहां पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जारी रखा ,बीटी. का कोर्स पूरा करने के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक रूप से समर्पित हो गए और प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में भेजे गये सन 1955 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के प्रान्त प्रचारक बनाए गये। पंडित दीनदयाल जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की और यहां से "राष्ट्र धर्म" नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया।

भारतीय जनसंघ की स्थापना

सन 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से असहमत होकर नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के सृजन के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प.पू.सरसंघ चालक श्री माधव सदाशिव राव गोलवलकर "श्री गुरु जी" से आदर्शवादी और देशभक्त नौजवानों को उपलब्ध कराने के लिए सहायता मांगी।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात से तत्त्वतः सहमत होते हुए संघ योजना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय,नाना जी देशमुख, अटल बिहारी बाजपेयी जी,सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशा भाऊ ठाकरे जी जैसे नौजवान प्रचारकों को राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के लिये भेजा गया।

इस राजनीतिक घटनाक्रम में दीनदयाल जी ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। दिनांक 21 सितंबर, 1951 के ऐतिहासिक दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक माह के बाद 21 अक्टूबर,1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।

दीनदयाल जी में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वह ऐतिहासिक दिन भी आया जब सन 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति का सन्देश लेकर दीनदयाल जी ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया।

11 फरवरी, 1968 का दिन देश के राजनीतिक इतिहास में एक बेहद दुःखद और काला दिन है। इसी दिन अचानक पंडित दीनदयाल जी की आकस्मिक मृत्यु हुई। वे मुगलसराय रेलवे स्टेशन (वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन) के निकट चलती रेलगाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गयी।

एकात्म मानवदर्शन

भाजपा संविधान की धारा तीन के अन्तर्गत 'एकात्मक मानवदर्शन" भाजपा का मूल दर्शन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने सुदीर्घ चिन्तन, अध्ययन एवं मनन के बाद सन् 1964–65 में विचारधारा के नाते इसका प्रणयन किया।

पाश्चात्य राजनैतिक चिन्तन ने मानव को 'सेक्यूलरवाद, व्यक्तिवाद (पूंजीवाद) समाजवाद एवं साम्यवाद की विचार धाराएं दी थीं। स्वतंत्र भारत का नेतृत्व भी इन्हीं वादों में भारत का भविष्य खोज रहा था। दीनदयाल जी ने इस खोज में हस्तक्षेप करते हुए यह सवाल खड़ा किया कि जब हमने पाश्चात्य साम्राज्यवाद को नकार दिया, तब अब हमारी क्या मजबूरी है कि हम पाश्चात्य वादों का अनुगमन करें।

सामान्यतः भारत के राजनैतिक क्षेत्र में स्थापित सभी दल यह सोचते थे कि हमें कुछ संशोधनों के साथ इन पाश्चात्य वादों को ही स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य चिंतन नहीं है। हम तो राष्ट्र थे ही नहीं। पाश्चात्यों ने ही आकर हमको राष्ट्र बनने के लिए तैयार किया है। उनका विचार है हम राष्ट्र बनने जा रहे हैं या हम नवोदित राष्ट्र है, आदि आदि।

भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि भारत एक प्राचीन एवं सनातन राष्ट्र है पश्चिम की राष्ट्र–राज्य परिकल्पना से पुरानी कल्पना भारत के 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की है। भारतीय संस्कृति की एक गौरवसम्पन्न ज्ञान–परम्परा हैं हमें इसी ज्ञान–परम्परा में भारत का भविष्य खोजना चाहिए।

मानव की तरफ देखने की पाश्चात्य दृष्टि खण्डित हैं उनका व्यक्तिवाद, समाजवाद का दुश्मन है तथा समाजवाद, व्यक्तिवाद का शत्रु है। वे प्रकृति पर मानव की विजय चाहते हैं, इस प्रकार यहां भी प्रकृति बनाम मानव उनका समीकरण है। सेक्यूलरवाद को अपना कर उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को अध्यात्म से काट लिया, अतः भौतिकवाद बनाम अध्यात्म, स्टेट बनाम चर्च तथा रिलिजन बनाम सांइस के द्वंद्वमूलक समीकरण वहां उत्पन्न हुये।

दीनदयाल जी मानते थे कि पश्चिम की यह बहस भी एक मानवीय बहस है, इसे हमें जानना चाहिए तथा इससे कुछ सीखना भी चाहिये, लेकिन हमें इन द्वंद्वमूलक निष्कर्षों का अनुयायी नहीं बनना चाहिये।

अतः मौलिक भारतीय चिन्तन के आधार पर विकल्प देने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं स्वीकार की। भारतीय जनसंघ की पहली पीढ़ी के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे। 1959 का पूना अभ्यासवर्ग, 1964 का ग्वालियर अभ्यास वर्ग तथा 1964 के संघ शिक्षा वर्गों के इस दृष्टि से विशेष महत्व है। इन वर्गों में परिपक्व हुये विचारों को दीनदयाल जी ने सिद्धांत और नीति प्रलेख में 'एकात्म मानववाद' नाम से प्रस्तुत किया। 1965 में भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा वार्षिक अधिवेशन में इसे मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया तथा 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे अपने मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया।

यह विचार "व्यक्ति बनाम समाज "नहीं वरन "व्यक्ति और समाज की एकात्मता" का विचार है। यह "मानव बनाम

प्रकृति" नहीं वरन "मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता" का विचार है। "भौतिक बनाम अध्यात्मिक "नहीं वरन इनकी एकात्मता का विचार है। भारत में इसे धर्म कहा गया है 'यतो अभ्युदय निःश्रेयस संसिद्धि स धर्म।' अर्थात् यह व्यष्टि, समिष्टि, सृष्टि व परमेष्ठी की एकात्मता का विचार है।

यह विचार दृश्यमान पृथकताओं में एकात्मता के सूत्र खोजता है। संसार में पृथकता नहीं विविधता हैं, जो 'पिंड' में है वही 'ब्रह्माण्ड' में है। आज मानव अपने को व्यक्ति मान कर अपनी सामाजिक संस्थाओं से युद्ध कर रहा है, परिवार, जाति, वंश , पंचायत सब को अपना दुश्मन मान रहा है। समाजवाद के नाम पर तानाशाहियों का सृजन कर रहा है, विकास के नाम पर प्रकृति से युद्ध कर रहा है, पर्यावरण का विनाश कर भयानक विभीषिकाओं को आमंत्रित कर रहा है। अध्यात्म का निषेध कर भोगेन्द्रियों का गुलाम बन रहा है। सुख की खोज में दुःख कमा रहा है तथा आनंद की अवधारणा से अपरिचित रह रहा है।

भारतीय परम्परा इन पृथकताओं का निषेध करती है वह जड़—चेतन सभी से अपनी रिश्ते स्थापित करती है। धरती 'माता' है चन्द्रमा मामा है पर्वत 'देवता' है, नदियां 'माता' है। समाज का हर व्यक्ति परस्पर जुड़ा हुआ है, यह संसार परायेपन की जगह नहीं, यह 'वसुधा तो एक कुटुम्ब' है आदि विचार मानव को असम्बद्धता, पृथकता तथा द्वन्द्वशीलता के सम्बंधों से निजात दिलाते है।

एकात्मता, समग्रता में निहित रहती है। समग्रता के अभाव में खण्ड दृष्टि से मानव आक्रांत होता है। जैसे ब्रह्माण्ड की समग्रता है, वैसे ही व्यक्ति की भी समग्रता है। व्यक्ति अर्थात केवल शरीर नहीं, उसके पास मन है, बुद्धि है और आत्मा भी है। यदि इन चारों में से एक की भी उपेक्षा हो जाये तो व्यक्ति का सुख विकलांग हो जायेगा। इन चारों के पृथक पृथक सुख से व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसे तो एकात्म एवं धनीभूत सुख चाहिये। जिसे आनंद कहते है। वैसे ही समाज केवल सरकार नहीं है, उसकी अपनी संस्कृति है, जन एवं देश है। इन चारों के सम्यक संचालन के बिना समष्टि के सुख का संधान नहीं होता।

इस प्रकार सृष्टि के पंच—महाभूत (पृथ्वी, जल, आकाश, प्रकाश व वायु) हैं, जिनके साथ न्याय—संगत व्यवहार होना चाहिये तथा अदृश्य किन्तु अनुभूति में आने वाले आध्यात्मिक तत्वों से भी योग्य साक्षात्कार होना चाहिये। तभी मानव सुखी होगा।

व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि तथा परमेष्ठी से एकात्म हुआ मानव ही विराट पुरुष है। इसके पुरुषार्थ चतुर्यामी है 'धर्म, अर्थ काम और मोक्ष' ये पुरुषार्थ मानव की परिस्थति निरपेक्ष आवश्यकतायें हैं, इनकी सम्पूर्ति करना समाज व्यवस्था का काम है।

धर्म—अर्थात शिक्षा—संस्कार एवं विधि व्यवस्था।

अर्थ—साधन पुरुषार्थ है। धर्मानुसार अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पदान, वितरण एवं उपयोग आदि।

काम—'धर्माविरुद्धो कामोऽहम' (जो धर्म के अविरूद्ध हैं, मैं वह काम हूँ—गीता) समस्त एषणायें इसके अन्तर्गत आती है, उनको सांस्कृतिक उपागम प्रदान करना संगीत एवं विविध कलाओं के माध्यम से एषणाओं को सकारात्मक बनाना। धर्म विरुद्ध काम पुरुषार्थ नहीं, वरन विकार है।

मोक्ष—परम पुरुषार्थ है, जब व्यक्ति अभाव व प्रभाव की कुण्ठाओं से मुक्त हो जाता है। अब इसे कुछ नहीं चाहिये **'विगतस्य कुण्ठः इति वैकुण्ठ।'**

यह विचार केवल प्रवचनों के लिए नहीं बल्कि यथार्थ राष्ट्रनीति एवं राजनीति का विषय है भारतीय जनता पार्टी की जब जब देश में सरकारें बनी उन्होंने इसे अपने केन्द्र में रखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में आई नई शिक्षा नीति जिसमें भारत केंद्रित शिक्षा को अपनाया गया है उसकी प्रेरणा एकात्म मानवदर्शन ही तो है।।

दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिश्रम और पुरुषार्थ का पर्याय था। वह कुशल संगठक एवं मौलिक चिंतक थे। सामाजिक सरोकार एवं संवेदना उनके संस्कारों में रची—बसी थी। एक राजनेता होते हुए भी उन्होंने जीवन और जगत के सभी पक्षों एवं प्रश्नों पर गहन चिंतन किया और उसका युगानुकूल चित्र खींचने और उत्तर देने का सार्थक प्रयास भी। और इस नाते वे एक राजनेता से अधिक राष्ट्र—ऋषि थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस भिन्न एवं विशिष्ट वैचारिक अधिष्ठान और मज़बूत सांगठनिक आधार पर खड़े और टिकी है, उसके वास्तविक शिल्पी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही थे। वह ऐसे राजनेता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, जिन्होंने न केवल स्वयं भारत को भारत के दृष्टिकोण स जानने—समझने—देखने की दृष्टि विकसित की, अपितु बहुतेरों को भी वैसी ही दृष्टि प्रदान की। भारत की चिति (आत्मा) एवं प्रकृति के मौलिक एवं सूक्ष्म द्रष्टा थे— पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वे सही अर्थों में व्यष्टि एवं समष्टि के शाश्वत सत्य एवं उनके पारस्परिक संबंधों को

समझ पाए थे। उस समझ को विकसित करने में उन्होंने सनातन संस्कृति के सदियों के अनुभव का विशद अध्ययन एवं साक्षात्कार किया।

दीनदयाल जी का मानना था कि चाहे वह पूँजीवाद हो या साम्यवाद, समाजवाद हो या व्यक्तिवाद, इन सभी दर्शनों की अपनी–अपनी कुछ सीमाएँ–लघुताएँ हैं। क्योंकि ये वाद के संकीर्ण–संकुचित दायरे में आबद्ध रही हैं, इनकी जड़ें विदेशी हैं और इन सबने भिन्न–भिन्न सभ्यताओं के मूल में स्थित दृ मनुष्य का चिंतन–विश्लेषण टुकड़ों में किया है। और जब तक मनुष्य का समग्रता एवं संपूर्णता से चिंतन नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी समस्याओं का भी संपूर्ण–समग्र समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

इसलिए उन्होंने मनुष्य का समग्र चिंतन करते हुए जिस दर्शन का प्रवर्त्तन किया, उसे पहले 'समन्वयकारी मानववाद' और बाद में 'एकात्म मानववाद' नाम दिया। चूँकि वाद की अवधारणा भारतीय मन एवं सनातन संस्कृति के अनुकूल नहीं, इसलिए आगे चलकर इसे 'एकात्म मानव दर्शन' कहा गया। उनका कहना था कि पश्चिमी जगत व दर्शन जीवन के सभी क्रियाकलापों के केंद्र में 'अस्तित्व के लिए संघर्ष' (स्ट्रगल फ़ॉर द एग्जिस्टेंस), 'शक्तिशाली का ही अस्तित्व' (सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट) 'प्रकृति का शोषण' (एक्सपलॉयटेशन ऑफ द नेचर) और 'वैयक्तिक अधिकार' (इंडिविजुअल राइट्स) को सर्वोपरि मानता आया है। जबकि दीनदयाल जी के मतानुसार अस्तित्व के लिए संघर्ष से अधिक सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। भारत की सनातन संस्कृति सर्वत्र सहयोग एवं सामंजस्य देखती आई है। उनका मानना है कि संपूर्ण जगत में जो संघर्ष एवं कोलाहल दिखाई देता है, वह मनुष्य की भेद–बुद्धि का परिणाम है। उनके अनुसार भारतीय जीवन–दृष्टि केवल शक्तिशाली के अस्तित्व की रक्षा में नहीं, अपितु सबके अस्तित्व की रक्षा में जीवन और जगत का कल्याण देखती है। इसीलिए यहाँ के चिंतन में सबसे पूर्व बाल–वृद्ध, अशक्त एवं दुर्बल की चिंता की गई है, न कि शक्तिशाली की। यहाँ प्रकृति को दासी या भोग्या नहीं, अपितु जीवन प्रदायिनी शक्ति या पालन–पोषण करने वाली जननी माना गया है। वैयक्तिक अधिकार से पूर्व भारत वर्ष में कर्तव्यों के पालन की परंपरा रही है। व्यक्ति परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में परिवार उसके अधिकारों की रक्षा करता है। परिवार समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में समाज उसके अधिकारों की रक्षा करता है। समाज राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में राष्ट्र उसके अधिकारों की रक्षा करता है और राष्ट्र विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में विश्व उसके अधिकारों की रक्षा करता है। इस प्रकार व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि तक संपूर्ण मानव–जाति अन्योन्याश्रित भाव से एक–दूसरे से जुड़ी है, एक–दूसरे पर निर्भर है। कोई किसी से विलग नहीं, कोई किसी से निरपेक्ष, स्वतंत्र या पृथक नहीं। संपूर्ण चराचर में व्याप्त उस एक ही सत्य या परम तत्त्व को पाने और देखने का दूसरा नाम ही एकात्म मानव दर्शन है। दरअसल एकात्म मानव दर्शन भारत की सनातन संस्कृति एवं सदियों से चली आ रही चिरंतन जीवन–पद्धत्ति की युगीन व्याख्या है। परस्पर सहयोग की भावना एवं ऊपरी भेदभाव से इतर कहीं गहरे में आंतरिक एवं तात्त्विक तौर पर एक –दूसरे से जुड़े होने के इस एकात्म भाव के कारण ही यह दर्शन वर्चस्ववादी, विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों एवं महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगा विश्व–बंधुत्व की भावना को सच्चे एवं वास्तविक अर्थों में साकार करता है।

पश्चिम ने मनुष्य को केवल शरीर तक सीमित करके देखा। कतिपय चिंतक मन और बुद्धि तक स्थूल रूप से पहुँचे अवश्य, पर वे आत्मा तक नहीं पहुँच सके। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं, अपितु शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। वह समान रूप से इन सबके सुखी होने पर ही सुख की गहरी एवं स्थाई अनुभूति कर सकता है। उसके कार्यों की प्रेरणा एवं जीवन के लक्ष्य को केवल भौतिक एवं ऐंद्रिक सुखों तक समेट देना उसकी सूक्ष्म एवं विराट चेतना को बहुत कम करके आँकना होगा। संसार की सभी महानतम उपलब्धियों के पीछे कोई–न–कोई महान प्रेरणा या ध्येयनिष्ठा काम करती आई है। व्यक्ति–मन में किसी एक क्षण की कौंध या संवेदना सामाजिक–जीवन में युगांतकारी बदलाव के कारण बनती है। विचारणीय है कि चाहे वह भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद का संघर्ष, बलिदान एवं उत्सर्ग हो; चाहे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी का साहस, शौर्य एवं पराक्रम हो; चाहे महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता का सेवा, त्याग एवं वैराग्य हो दृ क्या इन सबके पीछे की दृष्टि एवं प्रेरणा भौतिक या स्वकेंद्रित थी? मार्क्स की परिभाषा के अनुसार उन्हें रोटी–कपड़ा–मकान तीनों उपलब्ध थे? फिर क्यों उन्होंने ऐसा काँटों भरा संघर्षपूर्ण पथ चुना? किसी

महानतम प्रेरणा, शपथ युक्त संकल्प या देवदुर्लभ ध्येयनिष्ठा को सीमित संदर्भों में देखना–दिखाना उनके साथ सरासर अन्याय करना है। बल्कि आम आदमी के अनथक परिश्रम–पुरुषार्थ, भाग–दौड़, चाक–चिक्य के पीछे भी परिवार के सुख का प्रयोजन पहले आता है और अपने सुख का बाद में। बहेलिए के बाणों से बिद्ध क्रौंच पक्षी के करुण क्रंदन से व्यथित एवं द्रवित महर्षि बाल्मीकि के मुख से फूटी सहज काव्यधारा के पीछे कौन–सी प्रेरणा काम कर रही थी? क्या उसका कोई भौतिक–लौकिक कारण ढूँढा जा सकता है? उसे विद्वतजन जो भी नाम दें, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु है, जिसे देखने–समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए। आत्मा की दृष्टि चाहिए। 'आत्मवत सर्वभूतेषु' का यह भाव ही दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन का मूल मंत्र है। सबमें एक और एक में सबको देखना ही सनातन का परम लक्ष्य है। यही दीनदयाल जी के चिंतन का भी आधार था। इसीलिए वे गाँधी के 'सर्वोदय' से आगे 'अंत्योदय' की बात कर पाए। विकास की दृष्टि से हाशिए पर खड़ा अंतिम व्यक्ति उनके आर्थिक चिंतन का केंद्रबिंदु था। उसके विकास में वे समाज एवं राष्ट्र का वास्तविक विकास देखते हैं। वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय में से किसी की भी उपेक्षा नहीं करते। किसी को कमतर नहीं आँकते। उनका दर्शन काल्पनिक एवं वायवीय नहीं, यथार्थपरक एवं व्यावहारिक है। हिंसा, कलह एवं आतंक से पीड़ित मानवता के लिए उनका दर्शन एक वैश्विक वरदान है, समाधनपरक उपचार है। विभिन्न राजनीतिक दलों, कार्यकर्त्ताओं, नेताओं के लिए उनका व्यक्तित्व एक ऐसा दर्पण है, जिसमें देखकर–झाँककर वे अपना–अपना आकलन कर सकते हैं। बल्कि साधनों के पीछे भागते एवं भव्यता के आडंबर रचते दृ सभी दलों, नेताओं एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को वे सचेत एवं आगाह से करते प्रतीत होते हैं कि "प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा एवं सत्ता भी दृ साधनों से नहीं, साधना से मिलती है।"'

दीनदयाल जी ने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के एक मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। पूंजीवाद और समाजवाद की जगह पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ने स्वराज के रूप में गांधी जी द्वारा परिकल्पित नैतिक मूल्यों और लोकव्यवहार के आधार पर आर्थिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके लिए राजनीति जन सेवा का माध्यम थी। वे कहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति को जन सेवक के रूप कार्य करना चाहिए।

स्वदेशी आर्थिक मॉडल को अपनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एकात्म–मानववाद को रेखांकित किया। इसमें समावेशी और जन समुदाय को सशक्त बनाने का विचार था। उनका मानना था कि स्वदेशी और लघु उद्योग भारत की आर्थिक योजना की आधारशिला होनी चाहिए, जिसमें सद्भाव, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय नीति और अनुशासन का समावेश हो। स्वदेशी की प्राथमिकता रखते हुए वह विश्व स्तर पर हो रहे नवाचारों को अपनाने के भी कतई खिलाफ नहीं थे। हमारी जरूरतों की वस्तुओं का निर्माण भी देश में ही करना चाहते थे ताकि हम आत्मनिर्भर बनें। वे प्राकृतिक खेती के भी बहुत ही कद्रदान थे। वह जानते थे कि प्राकृतिक खेती से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि कृषि में टिकाऊ और लचीलापन आएगा।

> **भारतीयता, धर्म, धर्मराज्य, राष्ट्रवादी और अंत्योदय की अवधारणा से ही भारत को विश्व गुरु का स्थान हासिल हो सकता है।**

उनका मानना था कि भारतीयता, धर्म, धर्मराज्य, राष्ट्रवादी और अंत्योदय की अवधारणा से ही भारत को विश्व गुरु का स्थान हासिल हो सकता है। सभी के लिए शिक्षा और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के उनके दृष्टिकोण ने ही एक लोकतांत्रिक आर्थिक व्यवस्था में आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त किया है। पण्डित दीन दयाल जी एक ऐसी व्यवस्था के विरोधी थे जो रोजगार के अवसर को कम करती है लेकिन सामाजिक समानता, पूंजी और सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देने वाली भारतीय संस्कृति पर उनका विचार बिल्कुल स्पष्ट था। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में व ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में दीन दयाल उपाध्याय जी के पदचिन्हों का अनुसरण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ''लोकल से वोकल'' का सपना देखना वास्तव में हमारे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी की इस सोच में पण्डित दीन दयाल जी के विचार पूरी तरह झलकते है।

अंत में, मैं जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में उनके द्वारा कहे गए उनके शानदार शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा "हम किसी विशेष समुदाय या वर्ग की नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने शब्दों में "सबके साथ सबका विकास"कहा है। दीनदयाल जी की प्रतिज्ञा थी कि हमें हर भारतवासी को भारत माता की संतान होने पर गर्व का अनुभव करवाना है। हम भारत माता को ''सुजलां, सुफलां'' के वास्तविक अर्थों को धरातल पर उतारने में स्वयं को समर्पित कर देंगे। आइए हम एक आत्मनिर्भर और समावेशी भारत बनाने का संकल्प लें, जो पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

जनसभा
मुख्य अतिथि
मा. योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार
प्रत्याशी चन्द्रभानु

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2024-26
फरवरी प्रथम अंक 2025 –प्रेषित डाकघर –R.M.S. चारबाग, लखनऊ –प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।